www.dhyeyaias.com

मई 2020 | अंक 03

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 कोविड–19 का महिलाओं पर प्रभाव

एक अवलोकन

2 खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका की समस्या को उजागर करता कोविड–19

3 वैश्विक आतंकवाद सूचकांक पर नीति आयोग की आपत्ति

4 आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट : एक विश्लेषण

5 आरोग्य सेतु ऐप और गोपनीयता संबंधी मुद्दे

6 कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियाँ : चुनौती या अवसर

7 लॉकडाउन के कारण बदलता वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य

ध्येय IAS
most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।
इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।
हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।
इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।
'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर **'PERFECT 7'** में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन **'PERFECT 7'** को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए **'PERFECT 7'** पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय **IAS**

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने **'PERFECT 7'** पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। **'PERFECT 7'** पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। **'PERFECT 7'** के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। **'PERFECT 7'** के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त **'PERFECT 7'** पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय **IAS**

ध्येय IAS
most trusted since 2003

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	➢ विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	➢ क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	➢ कुरबान अली
प्रबंध संपादक	➢ आशुतोष सिंह
संपादक	➢ जीत सिंह ➢ अवनीश पाण्डेय ➢ ओमवीर सिंह चौधरी ➢ रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	➢ प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	➢ अजय सिंह ➢ अहमद अली ➢ स्वाती यादव ➢ अंशुमान तिवारी
लेखक	➢ अशरफ अली ➢ गिरराज सिंह ➢ हरिओम सिंह ➢ स्नेहा तिवारी
समीक्षक	➢ रंजीत सिंह ➢ रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	➢ संजीव कुमार झा ➢ पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	➢ गुफरान खान ➢ राहुल कुमार
प्रारूपक	➢ विपिन सिंह ➢ कृष्ण कुमार ➢ निखिल ➢ रमेश कुमार ➢ कृष्णकांत मंडल ➢ मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	➢ हरीराम ➢ राजू यादव

Content Office

ध्येय IAS
most trusted since 2003

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

मई 2020 | अंक 03

विषय सूची

7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–15

- कोविड–19 का महिलाओं पर प्रभाव: एक अवलोकन
- खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका की समस्या को उजागर करता कोविड–19
- वैश्विक आतंकवाद सूचकांक पर नीति आयोग की आपत्ति
- आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट : एक विश्लेषण
- आरोग्य सेतु ऐप और गोपनीयता संबंधी मुद्दे
- कोविड–19 से उत्पन्न परिस्थितियाँ : चुनौती या अवसर
- लॉकडाउन के कारण बदलता वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 16–22

7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 23–24

7 महत्वपूर्ण खबरें 25–28

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 29

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 30

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 31

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 कोविड–19 का महिलाओं पर प्रभाव: एक अवलोकन

संदर्भ

- कोविड-19 महामारी के चलते लाकडॉउन की स्थितियों ने महिलाओं के समक्ष कई चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं।
- कोविड-19 महामारी का प्रभाव समाज के लगभग सभी वर्गों पर पड़ा है, किन्तु इससे महिलाएँ अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित हुई हैं।
- महामारी के कारण महिलाओं को विभिन्न चुनौतियों से न सिर्फ भारत में बल्कि कमोवेश रूप से दुनिया के हर कोने में सामना करना पड़ रहा है।

महिलाओं पर प्रभाव

- कोविड-19 महामारी का महिलाओं पर प्रभाव को हम क्षेत्रवार रूप से देख सकते हैं:-

स्वास्थ्य

- भारतीय समाज में पराम्परागत रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। परिवार में यदि किसी महिला का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है और अकसर छोटे-मोटे घरेलू उपचारों से इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। अब जब कोविड-19 महामारी ने स्वास्थ्य संबंधी गंभीर चुनौतियों को उत्पन्न किया है तो इससे सबसे अधिक महिलाओं के प्रभावित होने की आशंका बढ़ गयी है।
- महिलाओं का प्रतिरक्षा तंत्र अपेक्षाकृत कमजोर होता है क्योंकि उन्हें समुचित मात्रा में पोषणयुक्त भोजन निरंतरता के साथ प्राप्त नहीं हो पाता है। वर्तमान में देखने में यह आ रहा है कि कोविड-19 महामारी उन्हें सबसे अधिक प्रभावित कर रही है जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है।
- भारत में स्वास्थ्य ढाँचा काफी कमजोर स्थिति में है अर्थात् स्वास्थ्य सेवाओं की यहाँ नितांत कमी है। देश में जो भी स्वास्थ्य संसाधन उपलब्ध हैं उनमें से अधिकतर कोविड-19 महामारी से निपटने में उपयोग हो रहे हैं, ऐसे में गर्भवती महिलाओं को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।
- एक अध्ययन के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर लगभग 70 प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मी महिला ही हैं जो कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने में कड़ी मेहनत कर रही हैं। इस स्थिति में उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा काफी अधिक बढ़ गया है।

रोजगार

- कोविड-19 महामारी ने अर्थव्यवस्था पर भारी चोट की है, इसलिए भारी संख्या में लोगों के रोजगार छिन रहे हैं; इनमें सबसे अधिक वह लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि असंगठित क्षेत्र, महिलाओं को सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के एक अनुमान के मुताबिक, कोविड-19 महामारी के चलते व्याप्त लॉकडाउन के कारण अगले तीन महीनों में वैश्विक रूप से लगभग 200 मिलियन रोजगार कम हो सकते हैं, इनमें बहुत से उन क्षेत्रों से संबंधित हैं जिनमें महिलाओं की भागीदारी अधिक है।
- अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में वे नौकरियाँ पहले जा रही हैं जो अपेक्षाकृत कम कुशल श्रम पर आधारित हैं। उल्लेखनीय है कि संगठित क्षेत्र में ज्यादातर महिलाएँ उन्हीं रोजगारों में संलग्न थीं जिनमें कम कुशलता की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूर्व में महिलाओं को शिक्षा और कुशलता प्राप्त करने के कम अवसर प्राप्त हो पाये हैं।
- निर्माण (Construction) क्षेत्र में महिला मजदूर भारी संख्या में नियोजित थीं लेकिन लॉकडाउन ने निर्माण क्षेत्र को काफी अधिक प्रभावित किया है, इस समय देश में निर्माण कार्य लगभग ठप्प हैं; इससे भारी संख्या में महिलाओं के रोजगार छिने हैं।
- आन्तरिक या बाह्य प्रवासन में सबसे अधिक संख्या पुरुषों की होती है। ग्रामीण क्षेत्रों से अधिकतर पुरुषों के प्रवासन के परिणामस्वरूप महिलाओं को घर से बाहर निकलकर कृषि कार्यों में संलग्न होना पड़ा अर्थात् कृषि क्षेत्र का महिलाकरण तेजी से हुआ (श्रम की पूर्ति हेतु)। लेकिन अब जब लॉकडाउन के कारण प्रवासी पुरुष मजदूर फिर से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर लौट रहे हैं तो महिलाओं के कृषि क्षेत्र से रोजगार छिनने की आशंका तेज हो गयी है।
- लॉकडाउन के कारण कई कम्पनियों ने मशीनीकरण पर जोर देना शुरू कर दिया है इससे भी महिलाओं के रोजगार प्रभावित होंगे।

शिक्षा

- शिक्षा पर महामारी का गहरा प्रभाव पड़ा है, वर्तमान में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। इसके कारण पहले से ही शैक्षणिक क्षेत्र में चुनौती का सामना कर रहीं महिलाएँ और अधिक प्रभावित हो सकती हैं।
- कई शैक्षणिक संस्थान ऑनलाइन एजुकेशन पर बल दे रहे हैं किन्तु इसके लिए न तो

महिलाओं के पास जरूरी संसाधन हैं और न ही सक्षमता है।

हिंसा

- कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की स्थिति ने वैश्विक स्तर पर महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा को बढ़ा दिया है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने एक अध्ययन में बताया कि भारत में लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के मामलों में दोगुनी वृद्धि हुई है। इसी प्रकार यूनाइटेड किंगडम में एक प्रमुख महिला हेल्पलाइन पर घरेलू हिंसा के मामलों की शिकायतों में लगभग सात गुना की वृद्धि दर्ज की गयी है।
- कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हुई है जिसने महिलाओं के प्रति साइबर हिंसा की सुभेद्यता को भी बढ़ा दिया है।

स्वतंत्रता

- पहले से ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही महिलाओं के लिए लॉकडाउन ने और अधिक मुसीबतें बढ़ायी हैं। अब उन्हें पुरुषों के अधिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है।
- उनकी निर्णय लेने की स्वतंत्रता पर भी चोट पहुँची है।

घरेलू कार्यों का बोझ

- लॉकडाउन के कारण महिलाओं पर घरेलू कार्यों का बोझ अधिक बढ़ गया है। घर पर बड़े-बुजुर्गों की सेवा से लेकर बच्चों की परवरिश तक महिला दिन-रात व्यस्त रहती है और लॉकडाउन की स्थिति ने इसमें और इजाफा किया है।

चुनौतियाँ

- वर्तमान में स्वास्थ्य व सफाई कर्मी, पुलिस आदि कोरोना वायरस की चुनौतियों से निपटने में अग्रणी भूमिका अदा कर रहे हैं, इनमें महिलाओं की संख्या भी काफी अधिक है; अतः अधिक घंटों की ड्यूटी, संक्रमण के प्रति सुभेद्यता आदि के बीच परिवार की जिम्मेदारी को निभाना उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है।
- दीर्घकालिक रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य, अधिकार, स्वतंत्रता, रोजगार, शिक्षा आदि पर नकारात्मक प्रभाव पूरे समाज को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।
- ऐसा माना जा रहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण कम हुए रोजगार के अवसर कार्यस्थल पर महिलाओं के शोषण को और अधिक बढ़ा सकते हैं।
- सरकार के पास महिलाओं से संबंधित चुनौतियों से निपटने हेतु संसाधनों की कमी है।
- महिलाओं से संबंधित सरकार के पास डाटा भी कम है जो उसे उपयुक्त नीति बनाने में बाधा उत्पन्न करता है।
- भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा आदि को रोकने हेतु कई कानून हैं लेकिन इनका वर्तमान में प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के मुताबिक, कोविड-19 के कारण आने वाली वैश्विक आर्थिक मंदी से महिलाएँ सबसे अधिक प्रभावित हो सकती हैं।

पहल

- यूरोपीय यूनियन और संयुक्त राष्ट्र संघ मिलकर स्पॉटलाइट एनिशिएटिव के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु वैश्विक स्तर पर प्रयास कर रहे हैं जिसे लगभग 25 देशों का समर्थन मिला हुआ है।
- भारत सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख का बीमा कवरेज प्रदान किया है।
- उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेण्डर वितरित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त नकद प्रत्यक्ष हस्तांतरण महिलाओं के जनधन खाते में किया जा रहा है।

आगे की राह

- सरकार को महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करना चाहिए तथा इनके द्वारा महिला उद्यमियों को आसान शर्तो और सस्ती ब्याज दरों पर सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- असुरिक्षत नौकरियों में महिलाओं को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए; उदाहरण के लिए सरकार जिन कम्पनियों को बेल आउट पैकेज प्रदान करे, उन्हें एक निश्चित संख्या में महिला कामगारों को रोजगार प्रदान करने की शर्त रखनी चाहिए।
- साामाजिक सुरक्षा एवं अन्य योजनाओं में महिलाओं के लिए विशेष उपबन्ध किये जाने चाहिए।
- कोविड-19 महामारी से लड़ने में महिलाएँ अग्रणी भूमिका निभा रही हैं तो ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- सरकार सहित सभी हितधारकों को महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु एक उपयुक्त नीति पर कार्य करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

प्र. कोविड-19 महामारी ने महिलाओं को किस प्रकार प्रभावित किया है? चर्चा करें।

02 खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका की समस्या को उजागर करता कोविड-19

चर्चा का कारण

- कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु वर्तमान राष्ट्रीय लॉकडाउन ने खाद्य, पोषण और आजीविका सुरक्षा की समस्याओं को उजागर किया है।
- वर्तमान में खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा संवेदनशील वर्ग गरीब, प्रवासी श्रमिक, भूमिहीन खेतिहर मजदूर, बच्चे आदि हैं।

खाद्य सुरक्षा

- खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य सभी व्यक्तियों को पूरे जीवन चक्र में निरंतरता के साथ पोषणयुक्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित होना है।
- खाद्य सुरक्षा के सामान्य सिद्धांत के अनुसार मुख्यतः तीन प्रमुख आयामों को शामिल किया जाता है-
  - भोजन की उपलब्धता (Food Availability)
  - भोजन तक पहुँच (Food Access)
  - भोजन का अवशोषण (Food Absorvation)

भोजन की उपलब्धता

- भारत में खाद्यान्न (अर्थात् भोजन) की उपलब्धता के मुद्दे को तीन चरणों में देखा जा सकता है-
  - आजादी के शुरूआती वर्ष
  - हरित क्रांति के बाद
  - वर्तमान स्थिति

आजादी के शुरूआती वर्ष

- आजादी के समय भारतीय कृषि काफी पिछड़ी अवस्था में थी, क्योंकि अंग्रेजों ने कृषि क्षेत्र का अत्यधिक शोषण किया था। आजादी के शुरूआती वर्षों में भारत में विदेशी व्यापार भी कम होता था, जिसके कारण कृषि क्षेत्र में बाहर से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नहीं आ सकी तथा यह क्षेत्र धीरे-धीरे पिछड़ता चला गया।
- आजादी के शुरूआती वर्षों में भारत के कृषि क्षेत्र में पिछड़ने के और भी कई कारण थे, यथा-भूमि सुधार कानूनों का लागू न हो पाना आदि। इस समय स्थिति यह थी कि भारत द्वारा खाद्यान्न का इतना भी उत्पादन नहीं किया जाता था कि देश के सभी नागरिकों की खाद्य जरूरतों को पूरा किया जा सकता; अर्थात् भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। भारत, अमेरिका से पीएल 480 कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न का आयात करता था; जिसका अमेरिका फायदा उठाकर भारत पर दबाव डालता था कि वैश्विक मुद्दों पर वह अमेरिकी नीतियों का समर्थन करे।

हरित क्रांति के बाद

- सन् 1960 के दशक के उत्तरार्द्ध में भारत में हरित क्रांति का दौर आया। हरित क्रांति के तहत किसानों को आधुनिक तकनीकें, उच्च गुणवत्ता के बीज, रासायनिक खाद आदि प्राप्त हुए। इससे भारतीय कृषि का परिदृश्य बदल गया।
- हरित क्रांति के बाद भारत न सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन के मामलें में आत्मनिर्भर बना बल्कि अब यहाँ से खाद्यान्न का निर्यात भी किया जाने लगा।
- हालाँकि हरित क्रांति का प्रभाव पूरे भारत में एकसमान नहीं रहा। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्र के किसानों ने इसका अपेक्षाकृत अधिक लाभ उठाया।

वर्तमान स्थिति

- अब हरित क्रांति का दूसरा चरण चल रहा है जिसमें उन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है जो प्रथम चरण में पिछड़ गये थे। इसके अतिरिक्त, अब संधारणीय कृषि के माध्यम से अधिक खाद्यान्न उत्पादन को सुनिश्चित किया जा रहा है।
- वर्तमान में भारत खाद्यान्न उपलब्धता के मामलें में काफी आगे है। सरकार द्वारा किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आवश्यकता से लगभग तीन गुना ज्यादा खाद्यान्न का भण्डारण किया जाता है। इस मामलें में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) एक नोडल एजेंसी है।
- वर्ष 2020-21 में रबी की फसल काफी अच्छी हुई है, जिससे पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्धता के संकेत मिलते हैं।

भोजन की उपलब्धता में चुनौतियाँ

- राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते भोजन या खाद्यान्न की उपलब्धता क्षेत्र में कई चुनौतियाँ सामने आयी हैं-
- लॉकडाउन के कारण श्रमिकों की गतिशीलता नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में कृषिगत कार्यों के लिए श्रमिकों की अनुपलब्धता हो गयी। पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों से प्रवासी मजदूरों की वापसी ने कृषि को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। जब कृषि कार्यों हेतु श्रमिकों की कमी होगी तो कृषि उत्पादन प्रभावित होगा जो खाद्यान्न उपलब्धता पर असर डालता है।
- लॉकडाउन के कारण कृषि में कई आगतें (यथा-उच्च गुणवत्ता के बीज आदि) मँहगी हो गयी हैं जो कृषि उत्पादन को प्रभावित कर रही हैं।
- आपूर्ति शृंखला प्रबंधन एवं परिवहन व्यवस्था के प्रभावित होने से जहाँ एक तरफ किसानों को

फसलों के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को ऊँचे दामों में खाद्य वस्तुओं को खरीदना पड़ रहा है।

- सरकार द्वारा वर्तमान में खाद्यान्न की खरीद भी अपेक्षाकृत कम की जा रही है, जिससे किसान अपनी फसलों को निजी व्यापारियों के हाथों सस्ते दामों में बेचने को मजबूर हैं।
- भारत में खाद्यान्न, फल, सब्जियों आदि सभी की निजी एवं सार्वजनिक दोनों ही भण्डारण अवसंरचना काफी कमजोर है, जिससे इन फसलों के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं शीत भण्डार गृह की अवसंरचना के कमजोर होने से शीघ्र नष्ट होने वाली खाद्य वस्तुओं (यथा-दूध, बागवानी फसल, सब्जी, फल आदि) को काफी नुकसान होता है।

भोजन तक पहुँच

- भोजन तक पहुँच का अभिप्राय है कि सभी लोगों को उचित कीमतों पर खाद्य पदार्थ नियमित तौर पर आसानी से प्राप्त हो सके। यदि खाद्य पदार्थो की उपलब्धता हुई लेकिन वह लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है तो भी खाद्य सुरक्षा संकट में पड़ जायेगी। 1940 के दशक में देश में भयंकर अकाल पड़ा था, विशेषज्ञों का कहना है कि इस अकाल से निपटने हेतु उस समय पर्याप्त खाद्यान्न था किन्तु ब्रिटिश सरकार के कुप्रबंधन के कारण लाखों लोग मारे गये।
- खाद्यान्न तक लोगों की आसान पहुँच बनाने हेतु सरकार सन् 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लेकर आयी थी। इस अधिनियम के तहत लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से सस्ती दरों पर आनाज उपलब्ध कराया जाता है।
- सरकार मध्यान्ह भोजन, आंगनवाड़ी आदि योजनाओं के तहत बच्चों को पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराती है, क्योंकि बच्चे कुपोषण के प्रति सबसे अधिक सुभेद्य होते हैं।
- सरकार द्वारा सभी लोगों के लिए आजीविका का प्रबंधन करना भी खाद्यान्न तक उनकी आसान पहुँच बनाने में मदद करती है। इसके लिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी को रोजगार उपलब्ध हो सके।

भोजन का अवशोषण

- यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि लोग जो भोजन का सेवन कर रहे हैं, उसका सही से पाचन अर्थात् अवशोषण होना चाहिए; तभी उसका लाभ मिल पायेगा।
- भारत में स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल आदि समस्याओं के कारण लोग भोजन को सही तरीके से नहीं पचा पाते हैं; इससे कुपोषण व अन्य तरह की स्थितियाँ पैदा होती हैं।

आगे की राह

- सरकार को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कृषि आगतों पर और अधिक सब्सिडी बढ़ानी चाहिए।
- खाद्य सुरक्षा, रोजगार उपलब्धता के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, अत: सरकार को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इससे न सिर्फ प्राथमिक खाद्य पदार्थो (यथा-दूध, फल आदि) का मूल्य संवर्द्धन होगा बल्कि भारी मात्रा में रोजगार उत्पन्न हो सकेंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाने हेतु मनरेगा योजना को कृषि एवं अन्य कुशलता वाले कार्यो में विस्तारित करना चाहिए।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कुछ और पोषणयुक्त पदार्थो को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि के लिए पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के बीच समन्वयन को बढ़ाया जाना चाहिए।
- सरकार को देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक उपयुक्त रणनीति बनानी चाहिए। इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकारों को मिलकर कार्य करना होगा।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे।
- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

प्र. खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? वर्तमान में भारत किस प्रकार की खाद्य चुनौतियों का सामना कर रहा है? चर्चा करें।

03 वैश्विक आतंकवाद सूचकांक पर नीति आयोग की आपत्ति

चर्चा का कारण

- ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित एक संस्था, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (जीटीआई) 2019 के अनुसार, आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में भारत सातवें स्थान पर है। इस रिपोर्ट पर नीति आयोग ने भारत को रैंक करने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है।

नीति आयोग का प्रश्नचिन्ह

- विदित हो कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, 2019 में भारत को विश्व के संघर्षग्रस्त देशों जैसे-डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, दक्षिण सूडान, सूडान, बुर्किना फासो, फिलिस्तीन और लेबनान आदि जैसे देशों की सूची में 7वें स्थान पर रखा गया है ।
- नीति आयोग की रिपोर्ट में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) की अपारदर्शी निधि पर भी सवाल उठाए गए हैं। नीति आयोग का कहना है कि IEP के फंडिंग स्रोतों के बारे में भी कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, ऐसे में उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा सकते हैं।
- नीति आयोग का मानना है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस (IEP) के द्वारा आतंकवाद से संबंधित जिस डेटाबेस का प्रयोग किया गया है वह पूर्ण रूप से अवर्गीकृत मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार हुआ है।
- जीटीआई प्रत्येक दिन प्रकाशित दो मिलियन से अधिक ओपन सोर्स मीडिया रिपोर्टों का विश्लेषण करने का दावा करता है, IEP की 2019 वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि संगठन में केवल 24 पूर्णकालिक कर्मचारी और 6 स्वयंसेवक हैं। नीति आयोग का कहना है कि यह वास्तव में आश्चर्य की बात है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक अवलोकन करने के लिए किस प्रकार यह संगठन लगभग 163 देशों के आंकड़ों का सार्थक विश्लेषण करने में सक्षम है और सिर्फ 24 स्टाफ सदस्यों और 6 स्वयंसेवकों के साथ देशवार आँकड़े एकत्रित करता है और फिर उनका विश्लेषण करता है।
- जीटीआई की गणना और उसके विश्लेषण में अस्पष्टता का एक बड़ा कारण यह है कि विभिन्न देशों के बीच आतंकवाद की परिभाषाओं में बड़ी विविधता है।

वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का महत्व

- ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स ऐंड पीस द्वारा प्रत्येक वर्ष वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (GTI) जारी किया जाता है, इसमें वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से संबंधित आँकड़ों के साथ-साथ विभिन्न देशों को आतंकवाद की स्थिति के आधार पर रैंकिंग भी दी जाती है। गौरतलब है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक के स्कोर को प्रत्यक्ष रूप से 'ग्लोबल पीस इंडेक्स' (Global Peace Index) और वैश्विक दासता रिपोर्ट (Global Slavery Report) में प्रयोग किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्द्धी सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक और सेफ सिटीज इंडेक्स (Safe Cities Index) में भी GTI का स्कोर अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है।

वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, 2019

- 2018 में भारत में आंतकवादी हमलों में लगभग 350 भारतीयों की जानें गई और 540 लोग जख्मी हुए। हालांकि भारत में आतंकवाद की वजह से मरने वाले लोगो की संख्या में गिरावट हुई है।
- 2018 में भारत में प्रति हमले औसतन 0-5 लोगों की मृत्यु हुई जबकि 1998 में यह आँकडा 4-3 लोगों का था।
- रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर भी आंतकवाद में कारण हुई मृत्युदर में गिरावट आई है।
- दक्षिण एशिया दुनिया का सबसे अधिक आंतक प्रभावित रहा जबकि मध्य अमेरिका सबसे कम आंतक प्रभावित क्षेत्र रहा।
- इस रिपोर्ट के मुताबिक आंतकवाद से प्रभावित देशों की संख्या में इस साल बढ़ोत्तरी हुई है तथा इनकी संख्या 67 से 71 हो गई है।
- 2018 में दुनियाभर मे आंतकवाद से मरने वाले की संख्या 15 प्रतिशत घटकर 15,952 हो गई है।

भारत में आतंकवादी घटनाएँ व सरकार की कार्यवाही

- 2019 में जम्मू-श्रीनगर हाइवे पर सुरक्षा बलों के ऊपर हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। ये आतंकवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष का एक निर्णायक मुकाम था। फरवरी 2019 में हुए इस आतंकवादी हमले ने नए साल की शुरुआत एक संकट

के साथ की थी और, इस की वजह से ही भारत ने पाकिस्तान के खैबर-पखतूनख्वा सूबे के बालाकोट में आतंकवादी शिविरों पर हवाई हमले किए थे। ये किसी आतंकवादी हमले के प्रति भारत की अभूतपूर्व प्रक्रिया थी। इस जवाबी हवाई हमले ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति में एक नया आयाम भी जोड़ा था।

- 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में इंडियन आर्मी के कैंप पर हमला किया था, जिसमें 18 जवान शहीद हो गए थे। 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक में 38 आतंकवादियों को मार गिराया गया। हमले में पाकिस्तानी सेना के 2 जवान भी मारे गए। इस ऑपरेशन में हमारे 2 पैरा कमांडोज भी लैंड माइंस की चपेट में आने से घायल हुए थे।

भारत को और सुरक्षित होने की जरूरत

- भारत में आतंकवाद का सबसे बड़ा खतरा सीमापार से प्रायोजित है। इस आतंकवाद को पाकिस्तान की सरकार से मदद और बढ़ावा मिलता है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का सब से बुरा प्रभाव कश्मीर घाटी को झेलना पड़ता है। 2019 में भारत ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म कर दिया। भारत सरकार के इस फैसले से पैदा हुए राजनीतिक हालात को अगर हम सुरक्षा के नजरिए से देखें, तो अभी इस का असर पूरी तरह से दिखना बाकी है।
- हालांकि, भारत के दृष्टिकोण से भी और अंतरराष्ट्रीय नजरिए से भी, आतंकवाद की चुनौतियों में विविधता आ रही है। विश्व स्तर पर बात करें तो, सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट (ISIS) के उभार में कमी देखी जा रही है।
- आतंकवाद से खतरों के पारंपरिक मोर्चों से ज्यादा आज भारत को दहशतगर्दी की वजह से पैदा हुए खतरों के नए मोर्चों पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि ऑनलाइन आतंकवाद। ऑनलाइन मोर्चे पर आतंकवादी समूहों का मुकाबला कर पाना अब तक मुश्किल साबित होता आया है क्योंकि आतंकवादी भी उसी तकनीक और उन्हीं माध्यमों का आपस में बातचीत और अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन से उन्हें परास्त करने की कोशिश की जा रही है। आज सोशल मीडिया का सोशल शब्द, दिनों दिन चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है।
- सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती ये है कि वो आम नागरिकों के निजता के अधिकार का उल्लंघन किए बिना, ऑनलाइन आतंकवाद की इन चुनौतियों से कैसे निपटें। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर बहस का ये एक अहम मुद्दा बना हुआ है। भारत इस मोर्चे पर खास तौर से पिछड़ा नजर आता है। भारत में नित नए निर्देशों के साथ नई एजेंसियां बनाई जा रही हैं। वहीं, पुरानी सुरक्षा एजेंसियों में सुधार किए बिना ही वो ऑनलाइन आतंकवाद का मुकाबला करने को मजबूर हैं। भारत में सुरक्षा का इकोसिस्टम, ऑनलाइन आतंकवाद से निपटने के लिए नए सक्षम और काबिल लोगों को अपने साथ जोड़ने में नाकाम रहा है।
- भारत में आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के अलावा बहुसंख्यकवाद की राजनीति भी सरकार के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर सकती है। एक ऐसा माहौल तैयार करना जिस में अल्पसंख्यक खुद को असुरक्षित महसूस करें, शोषण के कुछ मामले और भारत के अलग-अलग राज्यों में मुसलमानों के उत्पीड़न की घटनाओं से इस बात का डर है कि मुस्लिम समुदाय, इस्लामिक आतंकवादी संगठनों को रिझाने का अच्छा अवसर मुहैया कराएगा। हालांकि ऐतिहासिक रूप से हमने देखा है कि भारतीय मुसलमानों ने इस्लामिक आतंकवादी संगठनों और इन की विचारधाराओं को खारिज ही किया है।

आगे की राह

- भारत अगर आतंकवाद को केवल पाकिस्तान के संकीर्ण नजरिए से देखेगा, तो इसका मुकाबला करना मुश्किल होगा। हालांकि, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद भारत के लिए अभी भी सब से बड़ी चुनौती है। लेकिन, भारत को विश्व स्तर पर बढ़ रहे आतंकवाद के खतरों को देखते हुए, इसे समझने और इस आतंकवाद से निपटने के लिए भी तैयार रहना होगा, न कि वो खुद को केवल सीमा पार आतंकवाद पर ही केंद्रित रखें।
- भारत को ये भी ध्यान में रखना होगा कि स्थानीय आतंकवाद हो या सीमा पार से प्रायोजित दहशतगर्दी, दोनों को अलग कर के देखने में समझदारी नहीं है। आतंकवाद आगे चल कर कौन से रूप में सामने आएगा, इस की भविष्यवाणी कर पाना आसान नहीं है. हालांकि, आने वाले दशक में भारत को ऐसी क्षमता विकसित करने पर जोर देना चाहिए, जो 2019 के पहले बड़े आतंकवादी हमलों जैसी घटनाओं के खतरों को पहले से पहचान कर उन्हें नाकाम कर सके।
- इसके बाद ही भारत को आतंकवाद से निपटने के अपने पारंपरिक तौर-तरीकों में बदलाव लाने और आतंकवाद की नई चुनौतियों के प्रति अपनी जानकारी और सुरक्षा को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।
- भारत के हितों, भारतीय डायसपोरा पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव।

प्र. हाल ही में आईईपी द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया गया। नीति आयोग द्वारा इस सूचकांक को खारिज करने के कारणों का उल्लेख करें।

04 आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट : एक विश्लेषण

चर्चा का कारण

हाल ही में 'इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनीटरिंग सेंटर' (Internal Displacement Monitoring Centre-IDMC) ने 'ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटर्नल डिस्प्लेसमेंट-2020' (Global Report on Internal Displacement-2020) शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें कहा गया है कि 2019 में भारत में लगभग पांच मिलियन लोग विस्थापित हुए, जो विश्व में सर्वाधिक है।

भारत में विस्थापन

- इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण भारत में 2.6 मिलियन लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा।
- प्राकृतिक आपदा के कारण देश में लगभग 19,000 लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा।
- त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में राजनीतिक और चुनावी हिंसा के कारण 7600 से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, सामाजिक व आर्थिक भेद्यता, खतरे की तीव्रता एवं उच्च जनसंख्या विस्थापन के प्रमुख कारण थे।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 1901 के बाद से भारत में सातवां सबसे गर्म मौसम 2019 का था एवं इस वर्ष का मानसून 25 वर्षों में सबसे अधिक था।
- भारत ने वर्ष 2019 में आठ उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का सामना किया जिनमें माहा (केरल और लक्षद्वीप क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित) और बुलबुल (ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित) प्रमुख थे।

संघर्ष और हिंसा से आंतरिक विस्थापन

- 2019 में 50 देशों में (मध्यम आय वाले देश), जिसमें सीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) और इथियोपिया शामिल हैं, वहाँ एक मिलियन से अधिक नए विस्थापन हुए हैं।
- उप-सहारा अफ्रीका सर्वोच्च आंकड़ा वाला क्षेत्र था। साहेल में विशेष रूप से बुर्किना फासो, माली और नाइजर में हिंसा में वृद्धि और सुरक्षा में गिरावट से कई नए विस्थापन शुरू हो गए। सोमालिया और दक्षिण सूडान में चल रहे संघर्ष ने अपने घरों से सैकड़ों हजारों लोगों को भी विस्थापन के लिए मजबूर किया।

- सीरिया, यमन और लीबिया में लंबे समय से चल रहे संघर्षों के कारण मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में लोगों के विस्थापन में वृद्धि हुई है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार सभी क्षेत्र संघर्ष विस्थापन से प्रभावित हैं, लेकिन यह कुछ देशों में अत्यधिक केंद्रित है। वर्ष 2019 में 'संघर्ष और हिंसा' के कारण विस्थापित कुल 45.7 मिलियन लोगों में से तीन-चौथाई (34.5 मिलियन) विस्थापित लोग केवल 10 देशों से संबंधित हैं।

आपदाओं द्वारा आंतरिक विस्थापन

- वर्ष 2019 में 140 देशों और प्रांतों में प्राकृतिक आपदाओं से 24.9 मिलियन नए लोग विस्थापित हुए जिसमें 23.9 मिलियन लोग प्राकृतिक आपदा के कारण, जबकि शेष आगामी आपदा को देखते हुए विस्थापित हुए। यह विस्थापन 2012 के बाद सर्वाधिक है ।
- आपदा के कारण मुख्य रूप से विस्थापन निम्न और उच्च-आय वाले देशों में दर्ज किया गया था। चक्रवात ईदई (Idai) और केनेथ (Kenneth) ने मोजाम्बिक, मलावी, मेडागास्कर, जिम्बाब्वे और कोमोरोस और मैयट के द्वीप समूह के सैकड़ों लोगों को अपने घरों से विस्थापन के लिए मजबूर किया।
- बहामा को तूफान डोरियन ने काफी प्रभावित किया। इस तूफान ने पड़ोसी द्वीपों और अमेरिका और तथा में भी विस्थापन कर दिया।
- ऐसे समुदाय जो पहले से ही कमजोर थे वो लोग सर्वाधिक संख्या में विस्थापित हुए थे। दक्षिण सूडान में व्यापक बाढ़ ने उन लोगों को विस्थापित कर दिया जो पहले ही संघर्ष और हिंसा के कारण दूसरी जगह भाग गए थे। जनसंख्या के आकार के सापेक्ष, कोमोरोस में चक्रवात केनेथ के प्रभाव विनाशकारी थे।
- 95 देशों और क्षेत्रों में लगभग 5.1 मिलियन लोग वर्ष के अंत में आपदाओं के परिणामस्वरूप विस्थापन में रह रहे थे। इसमें वे लोग शामिल हैं जो 2019 में ही नहीं बल्कि पिछले सालों में भी आपदाओं में भाग गए थे।
- इस रिपोर्ट के मुताबिक कुल विस्थापितों में से 1.2 करोड़ बच्चे शामिल थे जिनमें से 38 लाख बच्चे संघर्ष एवं हिंसा के कारण विस्थापित हुए और 82 लाख बच्चे मौसम संबंधी आपदाओं के चलते विस्थापित हुए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि संघर्ष एवं हिंसा की तुलना में प्राकृतिक आपदाओं के कारण ज्यादा विस्थापित हुए।

इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनीटरिंग सेंटर

- आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IDMC) दुनिया के आंतरिक विस्थापन पर आकड़ों के संग्रह और विश्लेषण का आधिकारिक स्रोत है। इसे नार्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल' (Norwegian Refugee Council-NRC) के एक अन्य भाग के रूप में वर्ष 1998 में स्थापित किया गया था।
- आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र की स्थापना के बाद से ही यह संस्था विश्लेषित आँकड़ों की मदद से नीति निर्माण में देशों की मदद करता है ताकि भविष्य में विस्थापन के जोखिम को कम किया जा सके।
- IDMC की 2020 के आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट में अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी, यूरोपीय संघ, स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी, जर्मन संघीय विदेश कार्यालय, नॉर्वे का विदेश मंत्रालय, ऑस्ट्रेलिया का विदेश विभाग और व्यापार विभाग, अमेरिकी विदेश विभाग, शरणार्थी और प्रवासन विभाग ने सहयोग किया है।

आंतरिक विस्थापन का समाधान

- 2019 में आंतरिक विस्थापन को रोकने के लिए कई प्रयास दिखाई दिए, और कई देशों में विशेषज्ञों ने सफलता के लिए महत्वपूर्ण तत्वों पर प्रकाश डाला।
- नई राष्ट्रीय पहल ने राजनीतिक प्रतिबद्धता के अधिक स्तर को दिखाया। इसके अलावा आंतरिक विस्थापन पर नाइजर और सोमालिया जैसे देशों ने अपनी नीतिगत रूपरेखा में सुधार किया।
- अफगानिस्तान, इराक और फिलीपींस सहित अन्य देशों ने अपनी विकास योजनाओं में विस्थापन को शामिल किया, इसके अलावा सतत विकास लक्ष्यों पर भी ध्यान दिया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाइ फ्रेमवर्क के अनुरूप जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को अद्यतन करते समय इन देशों ने विशेषज्ञों से भी राय ली।
- मानवीय और विकास क्षेत्रों में मजबूत क्षमता, बेहतर समन्वय और निवेश बढ़ा कर इन देशों ने आपदा जोखिम को कम किया। अफगान सरकार आंतरिक विस्थापन को मानवीय और विकास दोनों के मुद्दे के रूप में समझती है, और इसे संघर्ष और आपदाओं के परिणामस्वरूप पहचानती है। इसमें संस्थागत समन्वय और प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने की क्षमता है।
- प्रभावी स्थानीय पहलों के लिए सटीक पूर्वानुमान और निरंतर धन की आवश्यकता होती है। हैती ने लंबी और अधिक पारदर्शी योजना रूपरेखा को सक्षम किया है, और सोमालिया में टिकाऊ समाधान के लिए स्थानीय संगठनों को संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष द्वारा समर्थन दिया गया है।
- देशों के बेहतर आपसी सहयोग द्वारा डेटा को अधिक उपलब्ध और सुलभ बनाया जा रहा है। अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका में क्षेत्रीय पहल सहयोग और समन्वय को मजबूत करते हैं, इसलिए ये तत्व डेटा को अधिक सुसंगत और विश्वसनीय बनाते हैं।
- विस्थापन पर लेखांकन एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो राजनीतिक प्रतिबद्धता को मजबूत करने और बनाए रखने के लिए जरूरी है। माली और फिलीपींस में राष्ट्रीय डेटा रणनीतियों और समर्पित बजट ने व्यवस्थित और नियमित रिपोर्टिंग को सक्षम किया है।

आगे की राह

- संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कोविड-19 को लेकर कई चेतावनी दी है। चूंकि बच्चे विश्व में अधिक संवेदनशील लोगों में से हैं। कोविड-19 उनके जीवन के लिए और नुकसान एवं अनिश्चितता लेकर आई है। इसके मुताबिक विस्थापन का दंश झेल रहे बच्चों और अन्य लोगों को इसकी वजह से ऐसी जगहों पर रहना पड़ता है जहां पर भीड़-भाड़ होती है। अकसर ये अस्थाई शिविर होते हैं जहाँ पर्याप्त साफ-सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं का भी अभाव रहता है। ऐसी जगहों पर न तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बताई गई एक दूसरे व्यक्ति से दूरी बनाए रखने के नियमों पालन हो सकता है और न ही दूसरे नियमों का यहां पर पालन किया जा सकता है।
- जब-जब इस तरह की वैश्विक महामारी का संकट आता है तब ऐसे ही बच्चे अधिक संवेदनशील होते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि विस्थापन के कारण उत्पन्न समस्याओं के निजात के लिए विभिन्न देशों की सरकारों को एक अलग प्रकार की नीति बनाए जाने का प्रयास करना चाहिए।
- निष्कर्षतः देखा जाये तो इस रिपोर्ट द्वारा अधिक राजनीतिक समर्थन की मांग की गयी है। इसमें विकास क्षेत्रों और मानवीय क्षेत्रों में निवेश में वृद्धि का भी सुझाव दिया गया है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

प्र. आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर विस्थापन की स्थिति तथा उससे उत्पन्न चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करें।

05 आरोग्य सेतु ऐप और गोपनीयता संबंधी मुद्दें

संदर्भ

- हाल ही में कोविड-19 द्वारा फैले सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के बीच, भारत में संघ और राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों जैसे लॉकडाउन, सामाजिक दूरी के मानदंडों, जियो-फेंसिंग, स्मार्ट फोन ऐप द्वारा निगरानी आदि को जनता द्वारा समर्थित किया गया है।
- इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार कोविड-19 से निपटने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय किये हैं, तथापि सरकार द्वारा किये प्रौद्योगिकी उपायों के कार्यान्वयन में उपयोग की जाने वाली विधियाँ, न्यूनतम कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने, मानवीय गरिमा और गोपनीयता के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को अनदेखा करती नजर आ रही हैं।

पृष्ठभूमि

- गौरतलब है कि राज्यों द्वारा महामारी से बचाव के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक लोगों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य डेटा पर आधारित है।
- मोटे तौर पर देखा जाय तो, इस तकनीक का उपयोग तीन स्तरों पर किया गया है:
  - COVID -19 से संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की सूची बनाने में।
  - क्वारंटाइन हुए व्यक्तियों (क्वारंटाइन इंडिविजुअल्स) की निगरानी के लिए जियो-फेंसिंग और ड्रोन इमेजरी को तैनात करने में।
  - स्मार्टफोन ऐप जैसे की आरोग्य सेतु के उपयोग के माध्यम से संपर्क-अनुरेखण (कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग) में।

विवाद क्यों है

- कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा तकनीकी का इस्तेमाल बढ़चढ़ कर किया जा रहा है। हालांकि तकनीकी इस्तेमाल पर विवाद भी काफी हो रहा है जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत देख सकते हैं-

संक्रमित व्यक्तियों की सूची

- संक्रमित व्यक्तियों की सूची बनाने में, राज्य लोगों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य डेटा का उपयोग करना चाहता है। यद्यपि 1897 की महामारी रोग अधिनियम राज्य को ऐसा करने की अनुमति देता है, परन्तु राज्य को संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक करने की शक्ति नहीं देता है क्योंकि यह किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का हनन करता है।
- सूचियों के जारी किया जाता है तो अन्य नुकसान भी उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 बीमारी के अलावा और किसी तरह के बीमारी का इलाज कराने में समस्या आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग बुखार खांसी जैसे लक्षणों को बताने से बच रहें हैं।

जियो-फेंसिंग और ड्रोन इमेजरी

- जियो-फेंसिंग और ड्रोन प्रौद्योगिकियों के संबंध में भी पर्याप्त कानून का अभाव है, वहीं उपयोग न के बराबर है।
- 1885 के टेलीग्राफ अधिनियम के तहत सेल-फोन आधारित निगरानी संभव हो सकती है, लेकिन अब तक इस तरह निगरानी वाले आदेश प्रकाशित नहीं हुए हैं।
- आधुनिक ड्रोन निगरानी जो निम्नलिखित क्षमता होने का दावा करती हैं:
  - थर्मल इमेजिंग का संचालन करने की क्षमता
  - रात के समय सर्वेक्षण की क्षमता
  - आधार जैसे मौजूदा डेटाबेस (कुछ निजी विक्रेताओं द्वारा दावा किया गया फीचर) में चेहरे की पहचान करने की क्षमता।
  - ध्यातव्य है कि 1934 के विमान अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के विपरीत इन ड्रोन के पास ना तो पर्याप्त अधिकार हैं ना ही लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। यहाँ तक कि ड्रोन के कुछ विशेष मॉडल को भारत में उपयोग भी नहीं दिया गया है। इसके अलावा इनके द्वारा आधार कार्ड द्वारा प्राप्त डेटा के दुरूपयोग की भी संभावना है।

संपर्क-अनुरेखण अनुप्रयोग

- केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु को अपना कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग ऐप बना लिया है जो महामारी से ग्रसित व्यक्ति का संकेत देता है।
- यह एप्लिकेशन उपयोगकर्ताओं को एक COVID-19 वाहक के गतिविधियों के प्रति

सूक्ष्म आकलन प्रदान करता है जिसका उद्देश्य कोविड-19 के संक्रमण को रोकना है।

- परन्तु अब तक, एप्लिकेशन की तकनीकी संरचना और उसके स्रोत कोड का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है।
- यह कार्यक्रम आधार कार्ड पर आधारित है परन्तु आधार कार्ड के आकड़ों को यह कितना सुरक्षित रख पाएगा यह चिंता का विषय है।
- आधार की तरह, अरोग्य सेतु को एक बड़े सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निजी गोपनीय जानकारी से युक्त किया गया है,लेकिन एक वैधानिक ढांचे के बिना और डेटा सुरक्षा कानून की अनुपस्थिति में इसका दुरुपयोग भी हो सकता है।

- डेटा अनामीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्तिगत डेटा को अपरिवर्तनीय रूप से इस तरह से बदल दिया जाता है कि डेटा के विषय को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य के द्वारा पहचाना नहीं जा सकता है।
- दुसरे शब्दों में कहें तो यह यह डेटा सेट से व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी को एन्क्रिप्ट करने या हटाने की प्रक्रिया है, ताकि जिन लोगों का डेटा संग्रहिते है वे अज्ञात रहें।

इस संबंध में परस्पर विरोधी तर्क क्या हैं?

- महामारी अस्तित्व के लिए खतरा बन रही है और इसलिए अन्य सभी हितों से पहले जीवन को बचाना सर्वोपरि है। यह इस विचार का समर्थन करता है कि यदि सरकार चाहे, तो मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है।
- परन्तु जस्टिस एचआर खन्ना द्वारा इंदिरा गांधी के आपातकाल पर दिया गया निर्णय इस संदर्भ में बहुत प्रासंगिकता रखता है। जस्टिस खन्ना ने कहा किसी हथियार के दम पर आजादी को नहीं कुचला जा सकता है। वे सरकार द्वारा आपदा को बहाना बनाकर विधि के शासन को नजरंदाज करने से भी चिंतित थे।

आरोग्य सेतु ऐप

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित आरोग्य सेतु ऐप को 2 अप्रैल को लॉन्च किया गया। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 14 अप्रैल, 2020 को राष्ट्र को अपने संबोधन के दौरान COVID-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए लोगों से ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से दूसरों को भी प्रोत्साहित करने के लिए कहा।
- यह ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है और अब तक 75 मिलियन लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं।
- आरोग्य सेतु सिंगापुर में ट्रेस टुगेदर नाम से इस्तेमाल किए जा रहे एक ऐसे ही ऐप से प्रेरित है, जिसे 21 मार्च को लॉन्च किया गया था और इसे सिंगापुर सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी GovTech ने विकसित किया था। इन दोनों ऐप में दो प्रमुख अंतर है:
  - ट्रेस टुगेदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए केवल ब्लूटूथ का उपयोग करता है जबकि आरोग्य सेतु जीपीएस का भी उपयोग करता है।
  - दोनों ऐप की गोपनीयता नीतियों में भी अन्तर है। ट्रेस टुगेदर में, डेवलपर्स स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे सीमित डेटा संग्रहीत करते हैं और ऐप के उपयोगकर्ताओं के बारे में अनावश्यक जानकारी एकत्र नहीं करते हैं। जबकि आरोग्य सेतु में इस बारे में अस्पष्ट है कि कौन सा सटीक डेटा एकत्र किया जाएगा और इसे कब तक संग्रहित किया जाएगा, इसका क्या उपयोग किया जाएगा या निजी संस्थाओं के साथ डेटा साझा करने में यह कितना पारदर्शी होगा।
- इसके अलावा आरोग्य सेतु में अद्वितीय डिजिटल पहचान (यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी) एक स्थिर संख्या (स्टेटिक नंबर) है, जिससे पहचान भंग होने की संभावना बढ़ जाती है। डिजिटल आइडेंटिटी लगातार बदलते रहना एक बेहतर कदम हो सकता है जैसे कि Google और Apple अपने संयुक्त संपर्क ट्रेसिंग तकनीक में उपयोग करते हैं।

- आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के उपयोग की शर्तों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उपभोक्ता जानकारी लीक होने या अनाधिकृत उद्देश्य के लिए इसके उपयोग किए जाने की स्थिति में सरकार ऐप के उपयोगकर्ता के लिए उत्तरदायी नहीं है।
- आरोग्य सेतु ऐप की गोपनीयता नीति के साथ एक और मुद्दा यह है कि भले ही इसमें कहा गया है कि डेटा का अनामकरण कर उसे भविष्य में उपयोग के लिए सरकार के पास संग्रहित किया जाएगा परन्तु यह इस प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक का उल्लेख नहीं किया गया है।
- डेटा का अनामकरण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि जब डेटा का उपयोग अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जाए, तो जिन लोगों से डेटा एकत्र किया गया है, उनकी पहचान उजागर न हो। हालाँकि डेटा अनामकरण भी डेटा की सुरक्षा के लिए सही साधन नही है। स्मार्टफोन ऐप से एकत्र बिग डेटा के आधार पर संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग हो सकता है।
- राज्य सरकारों द्वारा कोविड-19 से संबंधित ऐप को तैयार किया जा रहा है, परन्तु उनमें से कई के पास गोपनीयता नीतियां (प्राइवेसी पॉलिसी) और उपयोग की शर्तें (टर्म्स ऑफ यूज)भी नहीं हैं, जो इस महामारी के समय में व्यक्तिगत गोपनीयता के गंभीर उल्लंघन का कारण बन सकती हैं।

निष्कर्ष

- के एस पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने निजता के मौलिक अधिकार की गारंटी दी लेकिन न्यायालय ने यह भी माना कि वास्तव में यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है केवल संविधान ही इस अधिकार की एकमात्र संग्रहकर्ता नहीं है।
- यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि निजता का अधिकार निरंकुश नहीं है, ऐसी परिस्थितियाँ भी हैं जिनमें अधिकार को वैध रूप से घटाया जा सकता है।
- हालांकि, इस तरह के किसी भी प्रतिबंध के खिलाफ वैधता, आवश्यकता और आनुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर परीक्षण करना पड़ता है।
- इसके लिए सरकार को यह प्रदर्शित करना होता है कि -
  - प्रतिबंध, कानून द्वारा स्वीकृत है।
  - राज्य के न्यायसंगत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ही प्रतिबंध लगाया गया है।
  - राज्य ने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध "न्यूनतम प्रतिबंधात्मक" उपाय को चुना है।
  - उद्देश्य और लगाये गये प्रतिबंध के बीच विधि द्वारा मान्य तर्कसंगत संबंध है।
- हालाँकि, वर्तमान मामले में, सरकार के तकनीकी समाधान, कानून की दृष्टि में निराधार हैं। साथ ही साथ इस बात के संकेत बहुत कम है कि वे उपलब्ध न्यूनतम प्रतिबंधात्मक उपायों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
- एक महामारी के कारण संविधान में उल्लेखित विधियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। हमारा संविधान तो चाहे शांति का हो या संकट का, हर समय हमारे अधिकारों की रक्षा करता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस-अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याण कारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इस अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

प्र. महामारी और गोपनीयता के संदर्भ में इस बात का विश्लेषण करें कि महामारी के समय सरकार की प्राथमिकता व्यक्ति की गोपनीयता बनाये रखना है या उसकी जीवन सुरक्षा या फिर दोनो।

06 कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियाँ : चुनौती या अवसर

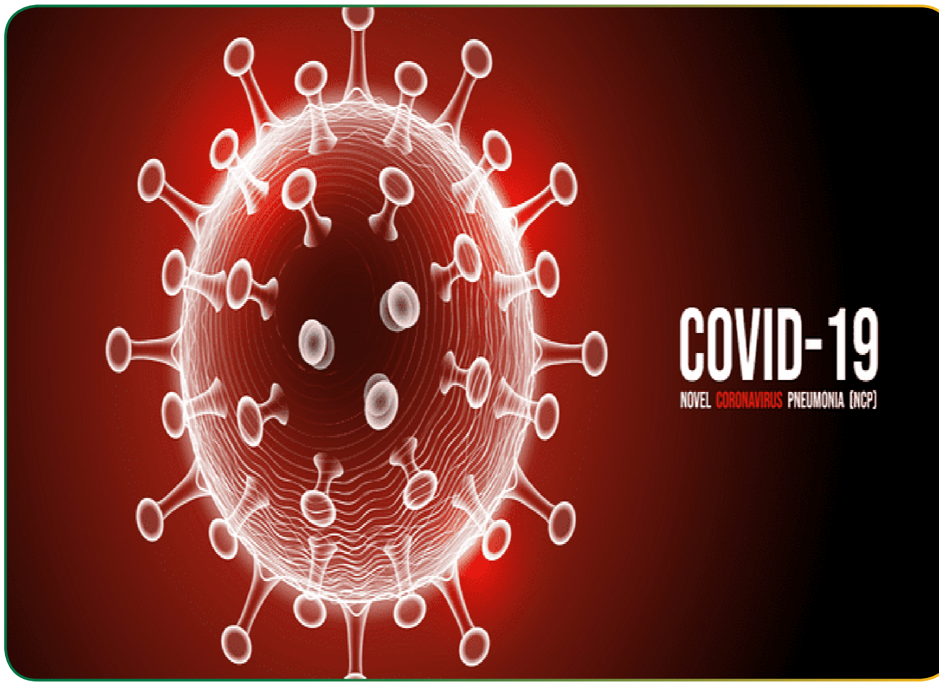

संदर्भ

- कोविड-19 के प्रकोप का भारत में अब तक कुशलता से प्रबंधन करने के लिए सरकार की सराहना करनी चाहिए। हालाँकि अर्थव्यवस्था पर इस वायरस के संभावित प्रभाव की भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन भविष्य में वैश्विक स्थिति बीते वर्षों के मुकाबले काफी अलग हो सकती है। भविष्य में भारी बदलावों के कारण भारत के लिए खुद को एक बेहतर और स्थायी आर्थिक महाशक्ति के रूप में बदलने के लिए उचित समय हो सकता है। ऐसा कई विशेषज्ञों का मानना है।
- इसमें कोई संदेह नहीं है कि विश्व के जीडीपी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और भारत को भी नुकसान होगा। परन्तु मुद्दा, अब नुकसान को कम करके और हमारे पास आने वाले कुछ अवसरों का सही दिशा में उपयोग करने का है।

वर्तमान स्थिति

- आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ द्वारा अनुमान किया गया है कि जीडीपी में गंभीर गिरावट हो सकती है।
- इसी प्रकार यूरोजोन ने अनुमान लगाया है कि 2020 में वैश्विक उत्पादन 7.5 प्रतिशत रहेगा जबकि अगले साल 4.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि संभावित है।
- भारत के संदर्भ में, साल के अंत में 1.9 प्रतिशत और 2021 में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। स्वास्थ्य सेवा पर अधिक ध्यान देना अनिवार्य है, क्योंकि इस तरह की महामारी भारत में पहले भी आ चुकी है जिससे लाखों जीवन काल के गाल में समा गये है, वर्तमान स्थिति एक वेक-अप कॉल (सीख लेने की आवश्यकता) की भांति है।

भारत की स्थिति

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में लिए गये निर्णय देश के भीतर निवेशकों को प्रभावित करने वाली सिद्ध होगी।
- भारत को अकसर "दुनिया की फार्मेसी" कहा जाता है, जो दुनिया के हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन (एचसीक्यू) का 70 प्रतिशत उत्पादन करता है।
- भारतीय फार्मा उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक है और देश का बाजार वैश्विक स्तर पर 60 प्रतिशत वैक्सीन का उत्पादन करता है।
- भारत को एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में कदम बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए भारत को अपनी आधारभूत संरचना में विकास करना होगा क्योंकि मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए, एक मजबूत आधार ही महत्वपूर्ण है।

भारत के लिए उभरते अवसर

- हालांकि, भारत में स्थिति जल्दी ठीक होने की उम्मीद है, हमें इसे साकार करने के लिए सम्मिलित प्रयास करने होंगे, जिसमें सार्वजनिक नीति समर्थन, निजी क्षेत्र की भागीदारी और नागरिकों के समर्थन के माध्यम से एकीकृत बहु-आयामी दृष्टिकोण शामिल होगा।
- यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है क्योंकि कई कंपनियां चीन से बाहर जाने की योजना बना रही हैं। भारत को इस तरह के निवेश का स्वागत करने के लिए तत्काल जमीनी स्तर की तैयार करनी होगी।
- वर्तमान में, दुनिया के अधिक से अधिक देशों में चीन के बारे में एक प्रतिकूल राय है और दुनिया इस वायरस के उद्भव और प्रसार में चीन की भूमिका के बारे में बहस करती रहेगी लेकिन यह स्पष्ट है कि चीन से बाहर अपने निवेश को स्थानांतरित करने के मामले में बड़ी संख्या में देशों ने पहले ही सोचना शुरू कर दिया है।
- भारत भी इस अवसर को लेने और सद्भावना का निर्माण करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है।
- भारत ने अपने कुछ अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करके इस क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ाया है। संक्षेप में कहें तो भारत अपनी प्राचीन संस्कृति "वसुधैव कुटुम्बकम" का प्रचार करता रहा है, जिसका अर्थ है "दुनिया एक परिवार है" और इस तरह की सद्भावना भारतीय विदेश नीति की विकसित प्रकृति को दर्शाती है।
- संकटकालीन समय में व्यक्तियों का वास्तविक व्यक्तित्व सामने आ जाता है। राष्ट्र-राज्यों के

मामले में भी ऐसा ही कुछ है, COVID-19 संकट के बीच चीन और अमेरिका दोनों एक दूसरे पर दोषारोपाण में संलग्न हैं लेकिन भारत ने टकराव की जगह सहयोग के दृष्टिकोण को चुना है।

- भारत के दृष्टिकोण ने भारत को ईरान और मलेशिया के देशों के साथ अपने संबंधों में अड़चनों को दूर करने का अवसर प्रदान किया है।

भारत की रणनीतिः पुनर्जीवित निकासी तन्त्र

- अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार को निम्नलिखित कदमों पर विचार करना होगा। ये कदम घरेलू निवेशकों को पुनर्जीवित करने में भी मदद करेंगे जैसे कि :

1. **जल्द से जल्द परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) को पुनर्जीवित करना**
   - यूपीए-2 के दौरान पीएमजी अस्तित्व में आया और इसने सही व्यवस्था करने में कामयाबी पाई।
   - प्रवर्तन एजेंसियां सिविल सेवकों को परेशान कर रही थीं जिससे कि निर्णय लेने की प्रक्रिया मे बाधा आ रही थी परिणामस्वरूप विभिन्न परियोजनाओं की मंजूरी अटक गई थी।
   - पीएमजी द्वारा योजनाओं के क्लीयरेंस के लिए एक पारदर्शी वेब-आधारित तंत्र लगाकर और राज्य सरकारों के साथ सघन रूप से क्लीयरेंस में तेजी लायी गयी। 15 महीनों की अवधि में 5 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
   - वाणिज्य और उद्योग (CII और FICCI) के दोनों प्रमुख चेम्बर्स ने भी अनुमोदित किया कि, "पीएमजी (PMG) रुकी हुई परियोजनाओं के लिए आवश्यक अनुमोदन और मंजूरी प्राप्त करने में एक अनुकरणीय भूमिका निभा रहा है।"
2. **सभी मंजूरियों को समयबद्ध और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना**
   - यह हरियाणा में पहले से ही समग्र फाउंडेशन द्वारा राज्य सरकार के साथ समन्वित रूप में किया जा रहा है।
   - पीएमजी में डेटा एकत्र होने से बाधाओं को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है।
   - ऊपर वर्णित सभी दोनों चरण आपस में जुड़े हुए हैं। इन कदमों से निवेशकों को सहूलियत मिलेगी। इससे निवेशक के पास अपने समस्याओं के निपटान के लिए संस्थागत तंत्र होगा।
   - समय के साथ, जैसे-जैसे प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित और डिजिटल होती जायेंगी, पीएमजी की भूमिका भी बदलती रहेगी।
3. **राजकोषीय और मौद्रिक उपाय**
   - उपरोक्त के अलावा, राजकोषीय और मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं, जिनसे निवेश को बढावा मिले।
   - राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण को सक्षम करने के लिए FRBM अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है।
   - निर्माण गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाने होंगे। हाल ही में पेट्रोलियम की कीमतों में हुई भारी गिरावट और बिटुमेन की कीमत में कमी का लाभ उठाया जा सकता है।

निष्कर्षः

- सरकार पहले से ही अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक पैकेज पर काम कर रही थी इसी का परिणाम है कि सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रूपये का आर्थिक पैकेज दिया गया है, जोकि निजी निवेशकों (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों) को कारोबार करने में सुविधा प्रदान करेगी।
- जमीनी स्तर पर कार्रवाई से क्या मदद मिल सकती है इसपर सरकार को ध्यान देना होगा क्योंकि यह देश और लोगों के हित में किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। वैसे तो दुनिया निश्चित रूप से हमेशा बदलाव से गुजरती है, लेकिन यह भविष्यवाणी करना मुश्किल है कि आखिरकार भविष्य में अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव क्या होगा। फिलहाल वर्तमान स्थिति के संकट को अवसर में बदलना हमारी इच्छाशक्ति पर निर्भर है।
- लॉकडाउन से सबसे अधिक पीड़ित गरीब असंगठित श्रमिक हैं, जिनमें से अधिकांश दैनिक-मजदूरी कमाने वाले हैं। ऐसे श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के मामले में देश को गंभीरता से सोचना होगा।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

प्र. "वैश्विक स्तर पर फैली कोविड-19 महामारी भारत के लिए एक बड़ी समस्या के साथ ही एक महत्त्वपूर्ण अवसर के रूप में भी है।" इस कथन से आप कितना सहमत हैं? चर्चा करें।

07 लॉकडाउन के कारण बदलता वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य

चर्चा का कारण

- हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) द्वारा 'वैश्विक ऊर्जा समीक्षा-2020' जारी की गयी।
- इस समीक्षा में कोविड-19 के कारण वैश्विक लॉकडाउन से वैश्विक ऊर्जा माँग (Global Energy Demand) और कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन (CO_2 Emmission) पर रिपोर्ट जारी की गई है।

कोविड-19 का वैश्विक ऊर्जा मांग (Global Energy Demand) पर प्रभाव

- नवीनतम आँकड़ों के अनुसार कोविड-19 के कारण वैश्विक आर्थिक गतिविधियों एवं आर्थिक गतिशीलता में कमी के कारण वैश्विक ऊर्जा माँग में भारी कमी दर्ज की गई। यह 2020 की प्रथम तिमाही में 2019 की प्रथम तिमाही के सापेक्ष 3.8 प्रतिशत कम है।
- आईईए के पूर्वानुमान के अनुसार, वर्ष 2020 में वैश्विक ऊर्जा मांग में 6 प्रतिशत की कमी देखी जा सकती है जो पिछले 70 वर्षों में सबसे अधिक होगी।
- वैश्विक अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की अधिक हिस्सेदारी वाले देशों में लॉकडाउन के दौरान प्रत्येक सप्ताह ऊर्जा की मांग में 25 प्रतिशत की गिरावट देखी जा रही है।
- भारत में लॉकडाउन के परिणामस्वरूप सेवा क्षेत्र में 30 प्रतिशत से अधिक की कमी देखी गई।
- वर्ष 2020 में कोरोना वायरस महामारी के कारण वैश्विक ऊर्जा की मांग में वर्ष 2008 के वित्तीय संकट की तुलना में सात गुना अधिक तक कमी देखी जा सकती है।
- चीन में आठ सप्ताह के लॉकडाउन के कारण ऊर्जा मांग में महत्त्वपूर्ण गिरावट रही जो 2020 में 2019 की प्रथम तिमाही की तुलना में 7 प्रतिशत की कमी रही। वर्तमान में चीन में साप्ताहिक ऊर्जा की मांग में लगभग 15% की गिरावट देखी जा रही है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कोविड-19 के प्रभाव के कारण मांग में लगातार गिरावट हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2020 की प्रथम तिमाही में ऊर्जा की माँग में 6 प्रतिशत की कमी अंकित किया गया है।
- यूरोप में लॉकडाउन को कठोरता से लागू किया गया है। यूरोप में पर्यटन अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसके साथ ही मार्च तक औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट के कारण यूरोपीय संघ में ऊर्जा की मांग में 5% की गिरावट को देखा गया। यूरोप में ऊर्जा की साप्ताहिक मांग में 15% की कटौती हुई है।
- कोरिया और जापान में लॉकडाउन के कम कड़े प्रतिबंधों के बावजूद ऊर्जा की माँग में 10 प्रतिशत तक की गिरावट हुई।
- 2019 के सम्पूर्ण वर्ष के सापेक्ष फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम की संयुक्त ऊर्जा मांग में वर्ष 2020 में 6% की गिरावट की संभावना व्यक्त की गई है।

ऊर्जा क्षेत्र पर मांग का प्रभाव

तेल क्षेत्र

- वैश्विक लॉकडाउन का सबसे ज्याद प्रभाव तेल क्षेत्र में देखा जा सकता है, क्योंकि वैश्विक तेल की लगभग 60 प्रतिशत खपत परिवहन, उड़ान और मालवाहन में से होती है।
- इस वर्ष तेल की मांग में 9% तक की कमी देखी जा सकती है, जो वर्ष 2012 के उपभोग के बराबर होगा।

कोयला क्षेत्र

- कोयले की मांग में 2019 के प्रथम तिमाही के सापेक्ष वर्ष 2020 में लगभग 8% तक की कमी हुई।
- इसका मुख्य कारण 2020 की प्रथम तिमाही में चीन में जो कि कोयला आधारित एक प्रमुख औद्योगिक देश है, में कोयले की मांग में आई कमी है। रिपोर्ट में इंगित किया गया है कि दक्षिण-पूर्व एशिया, इण्डोनेशिया और वियतनाम के बाजारों में सुधार, कोयले की मांग को बढ़ा सकते हैं।

विद्युत क्षेत्र

- वैश्विक ऊर्जा समीक्षा-2020 के अनुसार कुछ देशों में विद्युत क्षेत्र में 20% तक की कमी में हुई।
- इसका कारण, वैश्विक लॉकडाउन के कारण उद्योग क्षेत्र और व्यापार इकाईयों की बन्दी थी। विद्युत क्षेत्र की मांग में यह कमी 1929 के महामंदी के बाद सबसे ज्यादा देखी जा रही है।

प्राकृतिक गैस

- 2020 की प्रथम तिमाही में 2019 की प्रथम तिमाही की तुलना में प्राकृतिक गैस में 2 प्रतिशत गिरावट आयी है। चीन, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज्यादा मांग में गिरावट आयी है।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र

- विश्व के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में वर्ष 2020 के प्रथम तिमाही में महत्त्वपूर्ण गिरावट आयी, क्योंकि परमाणु ऊर्जा क्षेत्र विद्युत की मांग के साथ समायोजित है और विद्युत क्षेत्र में पहले से ही यूरोप व अमेरिका के देशों में अप्रत्याशित कमी हुई है।

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र

- 2020 की प्रथम तिमाही में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 1.5 प्रतिशत की वृद्धि पायी गयी है, जो पिछले वर्ष में पवन और सौर की नई परियोजनाओं के अतिरिक्त उत्पादन के कारण संभव हो पाया है।
- वैश्विक बंदी के बावजूद भी बेल्जियम, इटली, जर्मनी, हंगरी और अमेरिका में बिजली उत्पादन मिश्रण में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी में वृद्धि देखी गयी।

कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन पर कोविड-19 का प्रभाव

- वर्ष 2020 की प्रथम तिमाही में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी देखने को मिली है, यहाँ तक कि 2008 की आर्थिक मंदी की तुलना में 6 गुना ज्यादा कार्बन डाई आक्साइड में कमी हुई है।
- 2020 की प्रथम तिमाही में 2019 की प्रथम तिमाही के सापेक्ष कार्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन 5 प्रतिशत कम था, जो मुख्य रूप से ईंधन के प्रयोग में कमी के कारण हुआ। ईंधन के प्रयोग में कोयले में 8 प्रतिशत, पेट्रोलियम ईंधन में 4.5 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस में 2.3 प्रतिशत की कमी हुई।
- कोविड-19 के प्रभाव के कारण कार्बन उत्सर्जन में सबसे अधिक कमी क्रमशः चीन में (-8%) , यूरोपीय संघ में (-8%) और संयुक्त राज्य अमेरिका में (-9%) देखने को मिली है।
- 2020 के प्रथम तिमाही में कार्बन गहन ईंधन की मांग में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गयी और अतिरिक्त 9 महीनों में यह कमी बढ़ने की संभावना है। जिससे कार्बन उत्सर्जन में अभूतपूर्व कमी को देखा जा सकता है।

भारत पर ऊर्जा मांग का प्रभाव

- भारत में ऊर्जा मांग में 30 प्रतिशत से अधिक की कमी देखी गई है और लॉकडाउन आगे बढ़ने पर, प्रति सप्ताह के साथ ऊर्जा मांग में 0.6 प्रतिशत की गिरावट होने की संभावना है।
- ऊर्जा उद्योग की मूल्य शृंखलाएँ (Value Claim) आर्थिक बंदी के कारण वित्तीय रूप से प्रभावित हो सकती हैं। अधिकांश ऊर्जा कंपनियों के राजस्व में गिरावट देखी जा सकती है क्योंकि एक ओर तो ऊर्जा उत्पादों जैसे-तेल, गैस, कोयला और बिजली आदि की मांग में कमी हुई है वहीं दूसरी ओर इन उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट देखी गयी है।
- तेल की आपूर्ति और मांग में व्यापक कमी के कारण उत्पन्न होने वाले आर्थिक और वित्तीय व्यवधान से उद्योगों की उत्पादन क्षमता में कमी आ सकती है जिसके कारण देश की कुल उत्पादन क्षमता में बहुत कमी आ सकती है।
- ध्याव्य है कि भारत और चीन कोयला आधारित बिजली का दुनिया में अत्यधिक उपयोग करते है और कोयले की आपूर्ति में मांग और आकार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लॉकडाउन के कारण आर्थिक विकास और विद्युत उत्पाद में कोयले की मांग में गिरावट लाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण

- आईईए एक अन्तर्राष्ट्रीय निकाय है जिसकी स्थापना 1973 के अरब तेल गतिरोध, जिसके कारण वैश्विक तेल की कीमतों में अत्याधिक वृद्धि हुई। इस संकट के पश्चात् (OECD- Organisation for Economic Co-operation and development) सदस्यों द्वारा इसकी स्थापना 1974 की गई थी।

आईईए के प्रमुख कार्य

- आईईए ऊर्जा से संबंधित सभी विषयों का विश्लेषण करता है जैसे तेल, गैस और कोयला की आपूर्ति एवं माँग, नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक, बिजली, ऊर्जा क्षमता, ऊर्जा की उपलब्धता, मांग का प्रबंधन आदि।
- आईईए उन नीतियों का पक्षधर है जिनसे इसके सदस्य देशों और अन्य देशों में ऊर्जा की विश्वसनीयता, सुलभता एवं सतत वृद्धि हो।
- आईईए प्रशिक्षण एवं क्षमता वृद्धि के लिए कार्यशालाओं, भाषाओं एवं संसाधनों के कई कार्यक्रम चलाता ही है, इसके अतिरिक्त कुछ रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है जैसे-
  - विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण (World Energy Outlook)
  - आईईए मार्केट रिपोर्ट (IEA Market Report)
  - वैश्विक ऊर्जा समीक्षा (Global Energy Review)
  - मासिक खनिज तेल डाटा

आगे की राह

- ऊर्जा, आर्थिक गतिशीलता के मुख्य अवयव है जो कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन से मांग के गिरावट से प्रभावित है। आने वाले समय में स्वच्छ ऊर्जा, कम कार्बन डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन और बेहतर विनियामक प्रणाली, बाजार में उछाल के लिए उत्प्रेरक की भूमिका में होंगें।

सामान्य अध्ययन पेपर-3

Topic:

- संविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय।

प्र. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेन्सी द्वारा वैश्विक ऊर्जा समीक्षा रिपोर्ट 2020 जारी की गई। इस रिपोर्ट के आलोक में भारत में ऊर्जा की स्थिति की चर्चा करें।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 वार्षिक विशेष 301 रिपोर्ट

1. चर्चा का कारण

- संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USTR) ने अपनी वार्षिक विशेष 301 रिपोर्ट जारी की है।
- यूएसटीआर की वार्षिक विशेष 301 रिपोर्ट के अनुसार, भारत पर्याप्त बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन की कमी के लिए संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) की 'प्राथमिकता वॉच लिस्ट' पर कायम है।

2. क्या है स्पेशल 301 रिपोर्ट?

- यह संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि (USTR) के कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष तैयार की जाती है, जो अन्य देशों में बौद्धिक संपदा कानूनों जैसे कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क के कारण संयुक्त राज्य की कंपनियों और उत्पादों के लिए व्यापार अवरोधों की पहचान करती है।
- यह 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 के अनुसार प्रकाशित की जाती है।
- रिपोर्ट में 'प्राथमिकता वाले विदेशी देशों' की एक सूची शामिल है, जिन्हें अपर्याप्त बौद्धिक संपदा कानूनों के लिए आंका जाता है। ये देश प्रतिबंधों के अधीन हो सकते हैं।
- वार्षिक विशेष 301 रिपोर्ट में इन सूचियों के लिए यूएसटीआर ने 36 देशों की पहचान की, जिनमें से अल्जीरिया, अर्जेंटीना, चिली, चीन, भारत, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, यूक्रेन और वेनेजुएला प्राथमिकता वॉच लिस्ट में हैं।

3. भारत की स्थिति

- पर्याप्त बौद्धिक संपदा (IP) अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन की कमी के कारण भारत प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में बना हुआ है।
- हालांकि, भारत ने पिछले वर्ष में कुछ क्षेत्रों में आईपी संरक्षण और प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए सार्थक प्रगति की है ,परन्तु इसने लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों को हल नहीं किया,जबकि 2019 की रिपोर्ट में भी इसी प्रकार का आकलन किया गया था।
- भारत में ऑनलाइन आईपी प्रवर्तन में सुधार हुआ है, लेकिन प्रगति कुछ कारकों के कारण कमतर है जैसे–
  - अदालतों और पुलिस द्वारा कमजोर आईपी प्रवर्तन का उपयोग।
  - रिसर्च तकनीकों के साथ व्यवहारिकता का अभाव।
  - कोई केंद्रीकृत आईपी प्रवर्तन एजेंसी का न होना।
- यूएसटीआर भारत से ट्रेडमार्क संधि कानून पर सिंगापुर संधि में शामिल होने का आग्रह किया है, जो ट्रेडमार्क पंजीकरण में सामंजस्य स्थापित करता है।

4. यूएसटीआर

- यूएसटीआर संधि 28 मार्च 2006 को सिंगापुर में अपनाई गई थी और 16 मार्च 2009 को लागू हुई।
- जुलाई 2016 तक, संधि में अनुबंध करने वाले 50 दल थे, जिसमें 48 देशों के अलावा अफ्रीकी बौद्धिक संपदा संगठन और बौद्धिक संपदा के लिए बेनेलक्स (बेल्जियम, नीदरलैण्ड और लक्जमबर्ग) संगठन भी शामिल हैं।
- इसमें ट्रेडमार्क लाइसेंस की रिकॉर्डिंग पर प्रावधान शामिल हैं और जरूरतों के अनुसार रिकॉर्ड संशोधन या लाइसेंस का रिकॉर्ड रद्द किया जा सकता है।

02 मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी स्टेट

1. चर्चा का कारण

- ब्रिटेन के बाल चिकित्सा गहन देखभाल सोसाइटी (Paediatric Intensive Care Society-PICS) ने कहा कि उसने मल्टी-सिस्टम इन्फ्लेमेटरी स्टेट वाले बच्चों की संख्या में स्पष्ट वृद्धि देखी गयी है। डॉक्टरों का मानना है कि यह कोरोवायरस से संबंधित हो सकता है।

2. मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी स्टेट

- यह एक दुर्लभ बीमारी है जो रक्त वाहिकाओं की सूजन का कारण बनती है, जिससे निम्न रक्तचाप होता है।
- एक गंभीर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है जो पूरे शरीर को प्रभावित करती है क्योंकि यह फेफड़ों और अन्य अंगों में तरल पदार्थ का निर्माण करती है।
- इससे पीड़ित रोगियों को फेफड़ों, हृदय और अन्य अंगों को सहारा देने के लिए गहन देखभाल की आवश्यकता होती है।
- इस बीमारी के कारण बच्चों में विषाक्त शॉक सिंड्रोम और असामान्य कावासाकी रोग के परस्पर-व्यापी लक्षण दिखाई देते हैं।
- इसके अलावा पेट दर्द, गैस्ट्रो-इंटेस्टाइनल समस्याएं और हृदय की सूजन भी अन्य लक्षणों में देखा गया है।

3. विषाक्त शॉक सिंड्रोम

- इसके तहत जब कुछ बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करते हैं और हानिकारक विषाक्त पदार्थों को छोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति को विषाक्त शॉक सिन्ड्रोम कहते है। विषाक्त शॉक सिंड्रोम (Toxic Shock Syndrome-TSS) जीवन के लिए खतरनाक स्थिति है, यदि समय रहते इलाज नहीं किया गया तो स्थिति घातक हो सकती है।
- इसके लक्षणों में उच्च तापमान, फ्लू, सिरदर्द, गले में खराश, खांसी, दस्त, चक्कर आना या बेहोशी, साँस लेने में कठिनाई और भ्रमित होना (कन्फ्यूजन) जैसे लक्षण शामिल हैं। टीएसएस से पीड़ित कुछ रोगियों को आईसीयू में भी भेजना पड़ता है।

4. कावासाकी रोग

- कावासाकी बीमारी रक्त वाहिकाओं की एक तीव्र सूजन वाली बीमारी है और आमतौर पर पांच साल से कम उम्र के बच्चों में होती है।
- इसके अध्ययन व शोध के अनुसार कुछ डॉक्टरों का मत है कि यह बीमारी किसी संक्रमण के पश्चात प्रतिरक्षा प्रणाली के अति उत्तेजित होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली स्थिति है।
- इस रोग के कारण होने वाली सूजन शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करती है लेकिन हृदय पर इसका अधिक गंभीर प्रभाव होता है क्योंकि इससे कोरोनरी धमनियों(जो हृदय को रक्त की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होती हैं) में सूजन आ जाती है; इसके परिणामस्वरूप धमनीविस्फार (धमनी की दीवार में अत्यधिक सूजन) होने की संभावना बढ़ जाती है जो दिल के दौरे का कारण बन सकता है।
- इसके लक्षणों में बुखार, चकत्ते, कॉर्निया की लालिमा, लाल और फटे होंठ, लाल जीभ और गर्दन के लिम्फ नोड में वृद्धि शामिल है।

5. COVID-19 से संबंध

- इन लक्षणों वाले बच्चों में से कुछ ही कोविड -19 से संक्रमित हैं, इसलिए इससे अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि क्या और कैसे यह सिंड्रोम कोरोना वायरस से संबंधित है।
- ये रोग और स्थितियां दुर्लभ हैं, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि चिकित्सकों को किसी भी संभावित उभरते लिंक से अवगत कराया जाए ताकि वे बच्चों और युवाओं को समय पर सही देखभाल करने में सक्षम हों।

03 एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) संगठन ने कोविड-19 महामारी के कारण एशिया-प्रशांत क्षेत्र में 2.7 प्रतिशत आर्थिक गिरावट की उम्मीद व्यक्त की है।
- इस क्षेत्र में वर्ष 2009 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सबसे ज्यादा आर्थिक गिरावट की संभावना व्यक्त की गयी है।

2. कोविड-19 का एपेक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- APEC क्षेत्र में वर्ष 2019 की 3.8 प्रतिशत बेरोजगारी दर की तुलना में वर्ष 2020 में 5.4 प्रतिशत बेरोजगारी का अनुमान लगाया गया है।
- वर्ष 2021 के लिए एक आर्थिक रिबाउण्ड (Economic Rebound) की संभावना व्यक्त की गयी है, जिसमें एपेक (APEC) की 6.3 प्रतिशत विकास दर के साथ वैश्विक विकास दर में 5.8 प्रतिशत की उम्मीद की गई है।
- हालांकि यह आर्थिक रिबाउण्ड (Economic Rebound) कोविड-19 के प्रभाव को कम करने वाले तंत्र पर अधिक निर्भर करता है।

3. एपेक

- एपेक की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय क्वींसटाउन (सिंगापुर) में है।
- यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार तथा व्यावहारिक सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी मंच है।
- एपेक में वर्तमान में 21 देश शामिल है। इनके आलावा भारत सहित अन्य कई देशों ने भी एपेक की सदस्यता के लिए आवेदन किया है।
- एपेक का 31वाँ सम्मलेन नवम्बर 2019 में चिली में प्रस्तावित था जो रद्द हो गया था। 2020 में 32वाँ सम्मेलन मलेशिया में प्रस्तावित है।

4. एपेक के उद्देश्य

- विस्तृत आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना।
- एपेक क्षेत्र के बाजारोन्मुखी आर्थिक शक्तियों के बीच बहुपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहन देना।
- वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और तकनीक के आवागमन को प्रेरित करके सदस्य देशों के मध्य आर्थिक तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करना।
- एक उदार व्यापार और निवेश व्यवस्था विकसित करना।
- सदस्य देशों की सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना।
- एपेक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को पहचान कर, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और वन एवं समुद्री संसाधनों के स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देने का पहल करता है।
- एपेक, सदस्य देशों में महिला सशक्तिकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल कौशल प्रशिक्षण एवं उनके स्वनिर्मित उत्पादों की ब्रांडिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

04 राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) की रिपोर्ट

1. चर्चा का कारण

- वित्त मंत्रालय के अधीन एक सरकारी टास्क फोर्स द्वारा अगले पाँच वर्षों (2020-2025) में बुनियादी ढांचा के विस्तार और रोजगार सृजन के लिए अवसंरचना परियोजनाओं में कुल 111 लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान लगाया गया है।

2. पृष्ठभूमि

- वर्ष 2019 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बुनियादी ढाँचे में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की गयी थी।
- इसका मुख्य लक्ष्य जीवन स्तर में सुधार, व्यापार सुगमता एवं रोजगार के अवसर को बढ़ाना था।
- आर्थिक मामलों के मंत्रालय द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी, कार्यान्वयन एवं वित्त पोषण के लिए तीन समितियाँ बनायी गयीं थीं।
- ज्ञातव्य है कि दिसम्बर में जारी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में कार्यान्वित होने वाली विभिन्न परियोजनाओं में 102 लाख करोड़ रु के निवेश का अनुमान लगाया गया था।
- हाल ही में नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलान (NIP) की अंतिम रिपोर्ट जारी की गई जिसमें 2020-25 की अवधि के लिए अवसंरचना पर 111 लाख करोड़ निवेश का अनुमान लगाया गया है।

3. नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन रिपोर्ट

- एनआईपी रिपोर्ट में कुल आपेक्षित पूंजीगत व्यय के अंतर्गत-44 लाख करोड़ (एनआईपी का 40 प्रतिशत) की परियोजनाएँ क्रियान्वयन के लिए, 33 लाख करोड़ (एनआईपी का 30 प्रतिशत) वैचारिक संकल्पना के लिए, 22 लाख करोड़ विकासाधीन परियोजनाओं के लिए और 11 लाख करोड़ (NIP का 10 प्रतिशत) को अन्य कार्यों के लिए दिए जाएंगे।
- एनआईपी रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र पर 24 प्रतिशत, सड़कों पर 18 प्रतिशत, शहरीकरण पर 17 प्रतिशत और रेलवे पर 12 प्रतिशत निवेश का अनुमान लगाया गया है। लगभग ये क्षेत्र भारत के अनुमानित बुनियादी ढाँचा निवेश का लगभग 71 प्रतिशत भाग को आच्छादित (Cover) करते है।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के अंतर्गत केन्द्र सरकार की 39 प्रतिशत और राज्यों की 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी की योजना बनायी गयी है। इसके साथ ही निजी क्षेत्रों की 21 प्रतिशत हिस्सेदारी की भूमिका होगी।
- इस रिपोर्ट में भारत के बुनियादी ढांचे के सभी क्षेत्रों की पहचान की गई है एवं उनके प्रगति, धारा और चुनौतियों का गहन विश्लेषण किया गया है।
- संबंधित टास्क फोर्स द्वारा बुनियादी अवसंरचनाओं की रिपोर्ट को वित्त मंत्रालय के समक्ष को प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट में धन की जरूरतों को पूरा करने के लिए वॉण्ड बाजार, वित्तीय संस्थानों की स्थापना और भूमि मुद्रीकरण जैसे उपाय सुझाएं गए हैं।

4. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन

- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) एक निवेश योजना है जो केन्द्र सरकार द्वारा चिह्नित क्षेत्रो में 5 वर्षों के लिए निवेश बढ़ाने के लिए शुरू की गई है।
- इसके अंतर्गत ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों प्रकार की परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा।
- प्रत्येक संबंधित मंत्रालय/विभाग का यह दायित्व होगा कि वह परियोजनाओं का अनुश्रवण करे और यह सुनिश्चित करे कि उनका समय सीमा पर तथा निर्धारित लागत के अंदर कार्यान्वय हो जाये।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश के द्वारा 2024-25 तक पाँच ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के लक्ष्य को पुरा करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकता है।
- एनआईपी के अंतर्गत बिजली, नवीकरणीय, रेलवे, शहरी विकास, सिंचाई, गतिशीलता, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और डिजिटल क्षेत्र सम्मिलित हैं।

05 ATM स्किमिंग

1. चर्चा का कारण

- हम तेजी से डिजिटल इंडिया (Digital India) और कैशलेस सोसायटी (Cashless society) की तरफ बढ़ रहे हैं। कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) और लॉकडाउन (Lockdown) के चलते तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन (Online transaction) ही सुरक्षित लेनदेन का जरिया बनकर उभरा है।
- इस बीच ऑनलाइन फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। क्रेडिट (Credit card), डेबिट कार्ड (Debit card), इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking) फ्रॉड के मामलों में पिछले कुछ समय में लगातार इजाफा हुआ है।

2. एटीएम स्किमिंग क्या होती है?

- स्किमर एक मशीन होती है जिसमें एक कार्ड रीडर लगा होता है। इस स्किमर को एटीएम कार्ड रीडर में या कहीं ऊपर-नीचे लगा दिया जाता है। यह दिखने में कार्ड रीडर स्लॉट जैसा ही होता है इसलिए मशीन में कार्ड डालने वाले को पता नहीं चलता कि कोई गड़बड़ी है।
- जैसे ही कार्ड मशीन में डाला जाता है तो स्किमर इस कार्ड को रीड कर लेता है और डेबिट कार्ड का सारा डाटा चीटर्स के पास पहुंच जाता है। इस डाटा को एटीएम जैसे एक दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड में डाला जाता है। इसे क्लोन एटीएम कहते हैं। अब बारी आएगी पिन की। पिन की चोरी करने के लिए एटीएम के कीबोर्ड के ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा होता है।
- जब यूजर पिन डालता है तो यह कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर हैकर क्लोन एटीएम कार्ड से बड़ी आसानी से पैसे निकाल लेता है।

3. कार्ड क्लोनिंग

- कार्ड क्लोन करने के लिए स्कैनिंग स्लॉट वाली डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है।
- मशीन दिखने में PoS (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीनों की जैसी होती है।
- जालसाज डिवाइस के जरिए ग्राहकों के क्रेडिट-डेबिट कार्ड स्वाइप करते हैं।
- क्लोन कार्ड से भी अकाउंट से लेनदेन की जा सकती है।

5. एटीएम स्किमिंग से कैसे बचें?

- एटीएम पिन को दर्ज करते समय उसे ढक लेना चाहिए।
- मशीन पर कार्ड रीडर ढीला लगा हुआ तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
- बैंक ट्रांजेक्शन की तुरंत जानकारी SMS पर दी जानी चाहिए।
- एटीएम से रकम निकालने से पहले जांच लेनी चाहिए कि कोई स्कीमर तो नहीं है।
- स्वैपिंग प्वाइंट के अगल-बगल हाथ लगाकर देख लेनी चाहिए।
- मौजूदा समय में जरूरी है कि डेबिट कार्ड का पिन समय-समय पर बदल लेनी चाहिए।

6. एटीएम

- आटोमेटिड टैलर मशीन (एटीएम) को आटोमेटिक बैंकिंग मशीन, कैश पाइंट, होल इन द वॉल, बैंनकोमैट जैसे नामों से यूरोप, अमेरिका व रूस आदि में जाना जाता है।
- यह मशीन एक ऐसा दूरसंचार नियंत्रित व कंप्यूटरीकृत उपकरण है जो ग्राहकों को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराता है।

06 इम्युनिटी पासपोर्ट

1. चर्चा का कारण

- कोरोनावायरस (Coronavirus) ने पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लॉकडाउन के कारण कामकाज ठप होने से कई राष्ट्रों की आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कुछ जगहों पर कामकाज धीरे-धीरे शुरू किया जा रहा है। इसके लिए कुछ देश इम्युनिटी पासपोर्ट (Immunity Passport) के आइडिया पर विचार कर रहे हैं। इम्युनिटी पासपोर्ट या रिस्क फ्री सर्टिफिकेट (Risk Free Certificate) उन लोगों को जारी किए जाने की योजना है, जो कोरोनावायरस से जीतकर ठीक हो चुके हैं।

2. इम्युनिटी पासपोर्ट

- इम्युनिटी पासपोर्ट इंसान की इम्युनिटी पावर के आधार पर जारी किया जाने वाला एक मेडिकल सर्टिफिकेट है। यह एंटी बॉडी पर आधारित है।
- शरीर में हमेशा कोई न कोई वायरस हमला करता रहता है। ऐसे में एंटी बाडी उसका मुकाबला करता है। अगर एंटीबॉडी हार जाता है तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और अगर एंटीबॉडी जीत जाता है तो इसका तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति का एंटीबॉडी काफी शक्तिशाली है। ऐसे ही कोरोना वायरस के संक्रमण समय होता है। कोरोना वायरस हमला करता है तो व्यक्ति के अंदर की मजबूत एंटीबॉडी उससे लड़कर उसका खत्मा करने की क्षमता रखती हैं। ऐसे व्यक्ति के इम्युनिटी सिस्टम को मजबूत माना जाता है।
- यह एंटीबॉडी ही सफर पर जाने और आने का इम्युनिटी पासपोर्ट का काम करती है। दूसरे अर्थो में इम्युनिटी पासपोर्ट या रिस्क फ्री सर्टिफिकेट उन लोगों को जारी किए जाने की योजना है, जो कोरोनावायरस से जीतकर ठीक हो चुके हैं। ठीक हो चुके लोग एंटीबॉडीज के पर्याप्त रूप से विकसित होने के बाद रीइन्फेक्शन से सुरक्षित हैं, लिहाजा वे ट्रैवल करने या काम पर वापस लौटने में सक्षम हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि एंटीबॉडी बनने के बाद 80 से 90 फीसदी लोगों में संक्रमण की संभावना नहीं होगी, वह काम पर जा सकते हैं। पर एहतियात के साथ। एंटीबॉडी बनने की जांच के बाद इम्युनिटी पासपोर्ट जारी होगा।

3. WHO ने दी चेतावनी

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का कहना है कि सरकारों को कथित "इम्युनिटी पासपोर्ट" या "रिस्क फ्री सर्टिफिकेट" पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। WHO ने कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि जिन लोगों में संक्रमण से ठीक होने के बाद एंटीबॉडी विकसित हो गए हैं, उन्हें दोबारा संक्रमण नहीं होगा और वे कोविड-19 से सुरक्षित हैं। संगठन ने चेताया है कि इस तरह के कदम वायरस के संक्रमण को बढ़ाने वाले होंगे। जिन लोगों को लगेगा कि वे इम्यून हो गए हैं यानी रीइन्फेक्शन से सुरक्षित हैं, वे एहतियात बरतना बंद कर देंगे।
- WHO का कहना है कि सार्स (SARS) के मरीजों के दोबारा बीमार होने के कई मामले सामने आए थे। सार्स के मरीजों के शरीर में एंटीबॉडीज बनीं तो, लेकिन कई मरीजों में ये एक वक्त के बाद बेअसर हो गई। अब इस मामले में कोविड-19 के नतीजे आने बाकी हैं।

4. योजना जरूरी क्यों ?

- लॉकडाउन के कारण औद्योगिक उत्पादन ठप हो गया है। सामान्य दुकानों से लेकर स्कूल तक बंद हैं। द गार्जियन के अनुसार दुनिया को हर दिन अरबों डॉलर की आर्थिक चपत लग रही है। ऐसे में वर्क फोर्स को दोबारा काम पर लगाने की चुनौती है। जर्मनी ने इस दिशा में पहल की है। उसने इम्युनिटी पासपोर्ट योजना पर लॉकडाउन का फैसला करने के साथ ही काम करना शुरू कर दिया था। जिन लोगों के पास इम्युनिटी पासपोर्ट होगा उन्हें सबसे पहले काम पर आने का मौका मिलेगा।
- **ये कर रहे हैं शोध:** जर्मनी के रॉबर्ट रोच इंस्टीट्यूट, जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरस इंफेक्शन और बर्लिन के चौरिएट अस्पताल के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को जर्मनी के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस प्रोजेक्ट पर लगाया है। ब्लड डोनेशन में लगे एनजीओ से मदद ली जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सैंपल एकत्रित किए जा सकें। इस दौरान मानव शरीर में मौजूद लाखों तरीके की एंटी बॉडीज को पहचानने और उन्हें कोरोना से लड़ाई पर लगाने की युक्ति सोची जा रही है। स्वस्थ एंटी बॉडीज को पहचाना जाएगा, खासकर वे जो कोरोना के खिलाफ ताकतवर हैं।

07 COVID-19 के अपशिष्टों के निपटान की निगरानी

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्र और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के एक संयुक्त दल को कोविड-19 के अपशिष्टों को वैज्ञानिक तरीके से निपटा के निगरानी करने का निर्देश दिया है।

2. एनजीटी ने क्या कहा

- एनजीटी ने कहा कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम के तहत संक्रामक बीमारी से निपटने के दौरान उत्पन्न कचरे को ठिकाने लगाया जाता है जबकि कोरोना वायरस महामारी ने ऐसे उत्पन्न अपशिष्ट को वैज्ञानिक तरीके से निपटने की क्षमता के समक्ष चुनौती बढ़ा दी है।
- एनजीटी के अध्यक्ष न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि कोविड-19 के अपशिष्ट के वैज्ञानिक भंडारण, परिवहन, रखरखाव, प्रबंधन और निपटाने को लेकर करीबी निगरानी रखी जाए क्योंकि इसमें लापरवाही से पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा हो सकता है।
- पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर, पर्यावरण मंत्रालय, स्वास्थ्य, शहरी विकास, जल शक्ति, रक्षा और सीपीसीबी का एक उच्च स्तरीय कार्य दल कोविड-19 के अपशिष्ट को दिशानिर्देशों के तहत संभालने और वैज्ञानिक निपटान की निगरानी करे।
- पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि राज्यों के पर्यावरण विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करें और कार्रवाई की रिपोर्ट सीपीसीबी को प्रस्तुत करें।
- एनजीटी ने हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा कोविड -19 मरीजों की क्वारंटाइन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट के हैंडलिंग, उपचार और निपटान के लिए जारी किए गए उपायों का भी अवलोकन किया है।
- एनजीटी ने दिशानिर्देशों के संशोधन की आवश्यकता व्यक्त की ताकि तरल और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के वैज्ञानिक निपटान के सभी पहलुओं पर न केवल संस्थान स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर भी ध्यान रखा जाए, जैसे कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), इस्तेमाल किया बैग, दस्ताने, काले चश्मे आदि के निपटान के तरीके।
- एनजीटी ने कहा कि इसके लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाएँ और सम्बंधित स्थानीय निकायों और विभागों में प्रशिक्षण आयोजित किये जाएँ कोविड-19 कचरे को उठाने वाले कर्मियों को पर्याप्त सुरक्षा वस्त्र दिए जाएँ, मीडिया एवं नियामक प्राधिकरणों के बीच उचित समन्वय स्थापित किया जाए।

3. जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

- जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में यह प्रावधान है कि प्रयोगशालाओं से निकलने वाले कचरे, सूक्ष्म जीवाणु कचरे, रक्त के नमूनों और रक्त की थैलियों को प्रयोगशाला में ही संक्रमण मुक्त कर दिया जाना चाहिए।
- स्वास्थ्य कार्य से जुड़े कर्मियों को नियमित रूप से रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए टीका आदि दी जाए और इसके लिए उन सभी को प्रशिक्षित किया जाए। इसके अतिरिक्त जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमवाली के अनुसार, निपटान के लिए जाने वाले जैव-चिकित्सा कचरे के लिए जो थैलियाँ या डिब्बे होंगे उन पर बारकोड अंकित होना चाहिए।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) राज्यों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये सभी संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रदूषण नियंत्रण समिति (State Pollution Control Boards- SPCB and Pollution Control Committees- PCC) के साथ काम कर रहा है।
- कोविड 19 के इलाज में प्रयोग किए गए संसाधनों में दूषित अपशिष्ट, ट्यूबिंग जैसे डिस्पोजेबल आइटम से उत्पन्न कचरा, सीरिंज, पेशाब की थैलियाँ, दस्ताने इत्यादि अपशिष्ट शामिल हैं।
- गौरतलब है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट को निम्न 4 श्रेणियों में बाँटा गया है-
  - **येलो श्रेणी:** इसमें पशु अपशिष्ट, मिट्टी का कचरा, एक्स्पायर्ड दवाएँ, रासायनिक कचरा, रासायनिक तरल अपशिष्ट, और अन्य नैदानिक प्रयोगशाला अपशिष्ट आदि शामिल हैं।
  - **रेड श्रेणी:** इसमें दूषित अपशिष्ट, ट्यूबिंग जैसे डिस्पोजेबल आइटम से उत्पन्न कचरा, सीरिंज, पेशाब की थैलियाँ, दस्ताने इत्यादि अपशिष्ट शामिल हैं।
  - **ब्लू श्रेणी:** इसमें नुकीली धातुओं (इन्जेक्शन के निडिल्स, टाँके की सूई) वाले अपशिष्ट शामिल हैं।
  - **व्हाइट श्रेणी:** इसमें काँच के बने पदार्थों के अपशिष्ट शामिल हैं।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 वार्षिक विशेष 301 रिपोर्ट

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वार्षिक विशेष 301 रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
2. इस रिपोर्ट के माध्यम से अमेरिका अपने व्यापारिक भागीदारों का बौद्धिक संपदा रक्षा और व्यापार प्रवर्तन का आंकलन करता है।
3. रिपोर्ट की 'प्राथमिक वॉच लिस्ट' में भारत को स्थान नहीं दिया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3 (d) उपरोक्त सभी

उत्तरः (b)

व्याख्याः हाल ही में संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USTR) द्वारा वार्षिक विशेष 301 रिपोर्ट जारी किया गया। इस रिपोर्ट के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका अपने व्यापारिक भागीदारों का बौद्धिक सम्पदा रक्षा और व्यापार प्रवर्तन का आंकलन करता है। पर्याप्त बौद्धिक सम्पदा (IP) अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन में कमी के कारण भारत 'प्राथमिक वॉच लिस्ट' में 36 देशों के साथ लिस्ट में बना हुआ है। इस तरह से कथन 1 व कथन 3 गलत है, अतः उत्तर (b) होगा।

02 मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी स्टेट

प्र. मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी स्टेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी स्टेट के लक्षण ब्रिटेन के बच्चों में देखे गए।
2. इस बीमारी में रक्त वाहिकाओं में सूजन और निम्न रक्तचाप की समस्या पायी जाती है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/ हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः ब्रिटेन में कुछ बच्चों के रक्तवाहिकाओं और कोरोनरी आर्टरीज में सूजन देखा गया। इसके अध्ययन व शोध के अनुसार कुछ डॉक्टरों का मत है कि यह बीमारी किसी संक्रमण के पश्चात प्रतिरक्षा प्रणाली के अति उत्तेजित होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली स्थिति है। इस बीमारी में फेफड़ों में तरल पदार्थ का निर्माण होने लगता है। इस तरह कथन 1 और कथन 2 सही हैं, अतः उत्तर (c) होगा।

03 एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग

प्र. एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत, एपेक संगठन का संस्थापक सदस्य है।
2. एपेक, संपूर्ण विश्व में मुक्त व्यापार तथा व्यावहारिक सहयोग को प्रोत्साहन देता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (d)

व्याख्याः एपेक की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। एपेक संगठन में वर्तमान में 21 देश है। भारत एपेक की सदस्यता के लिए आवेदन किया है (वर्तमान में सदस्य नहीं है)। एपेक सिर्फ एशिया-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार तथा व्यावहारिक सहयोग को प्रोत्साहन देता है। इस प्रकार दोनों ही कथन गलत हैं, अतः उत्तर (d) होगा।

04 राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) की रिपोर्ट

प्र. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) की रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वित्त मंत्रालय के अधीन एक सरकारी टास्क फोर्स द्वारा बुनियादी ढाँचा बढ़ाने तथा रोजगार सृजन के लिए 111 लाख करोड़ की योजना की अवधि 2020-2030 है।

2. इस नीति के अंतर्गत सबसे ज्यादा निवेश ऊर्जा क्षेत्र पर किया जाएगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनो (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (b)

व्याख्या: वित्त मंत्रालय के अधीन एक सरकारी टास्क फोर्स द्वारा अगले पाँच वर्षो 2020 से 2025 में बुनियादी ढाँचा बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए अवसंरचना परियोजना में कुल 111 लाख करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान लगाया गया है। इसमें 24 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र पर, 18 प्रतिशत सड़को पर, शहरीकरण पर 17 प्रतिशत तथा रेलवे पर 12 प्रतिशत निवेश की योजना है। इस तरह कथन 2 सही है, अत: उत्तर b होगा।

05 ATM स्किमिंग

प्र. ATM स्किमिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसमें हैकर, कार्ड स्किमर के द्वारा डेबिड कार्ड, क्रेडिट कार्ड की जानकारी ATM मशीन में कार्ड डालते ही प्राप्त कर लेता है।
2. स्किमिंग के बाद ATM कार्ड की पिन को चोरी करने के लिए हैकर कीबोर्ड के ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा देता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: स्किमर एक मशीन होती है जिसमें एक कार्ड रीडर लगा होता है। जैसे ही ATM कार्ड मशीन में डाला जाता है तो स्किमर इस कार्ड को रीड कर लेता है और एटीएम कार्ड का सारा डाटा हैकर के पास पहुंच जाता है। इसके बाद पिन की चोरी करने के लिए हैकर एटीएम के कीबोर्ड के ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा देते है। इस तरह से दोनों कथन सही हैं अत: उत्तर (c) होगा।

06 इम्युनिटी पासपोर्ट

प्र. इम्युनिटी पासपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इम्युनिटी पासपोर्ट कोविड-19 से रिकवर हुए मनुष्य की इम्युनिटी पावर पर आधारित जारी किया जाने वाला एक मेडिकल सर्टीफिकेट है।
2. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने कोरोना वायरस के विरुद्ध इम्युनिटी पासपोर्ट को प्रमाणित किया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या: कोरोना वायरस की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था अत्यधिक प्रभावित हुई है। ऐसे में कुछ देश इम्युनिटी पासपोर्ट पर विचार कर रहे हैं जो मनुष्य के इम्युनिटी पॉवर पर आधारित एक मेडिकल सर्टीफिकेट है। WHO ने “इम्युनिटी पासपोर्ट” या “रिस्क फ्री सर्टिफिकेट” को प्रभाणित नहीं किया क्योंकि कोविड-19 के संक्रमण रिकवर के बाद रीइन्फेक्टेड की संभावना बनी हुई है। इस प्रकार कथन b गलत है, अत: उत्तर (a) होगा।

07 COVID-19 के अपशिष्टों के निपटान की निगरानी

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अनुसार प्रयोगशालाओं के कचरे को प्रयोगशाला में ही संक्रमणमुक्त कर देना चाहिए।
2. कोविड-19 के इलाज में प्रयोग किए गए संसाधनो से दूषित अपशिष्ट के निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने संस्थागत एवं व्यक्तिगत निपटान के लिए गाइडलाइन (दिशा-निर्देश) जारी किया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 में यह प्रावधान है कि प्रयोगशालाओं से निकलने वाले कचरे, रक्त के नमूनें और रक्त की थैलियों को प्रयोगशाला में ही संक्रमणमुक्त कर देना चाहिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने केन्द्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड (CPCB) के एक संयुक्त दल को कोविड-19 के अपशिष्ट को दिशानिर्देशों के तहत संभालने और वैज्ञानिक निपटान करने का निर्देश दिया हैं इस तरह से दोनों कथन सत्य हैं, अत: तरह उत्तर (c) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 मणिपुर काला चावल, गोरखपुर का टेराकोटा, तमिलनाडु के कदलाई मितई और कश्मीरी केसर को GI टैग

- हाल ही में मणिपुर के काले चावल (चक-हाओ), गोरखपुर का टेराकोटा और कोविलपट्टी की कदलाई मितई को भौगोलिक संकेत (GI Tag) प्रदान किया गया।

काला चावल

- इस चावल की किस्म का रंग गहरा काला होता है और अन्य चावल की किस्मों जैसे भूरे चावल आदि की तुलना में इसका वजन अधिक होता है। एंथोसायनिन एजेंट के कारण इसका रंग काला होता है। यह चावल मिष्ठान, दलिया बनाने के लिए उपयुक्त है। यह चीन की पारंपरिक रोटी, नूडल्स और राइस केक व्यंजनों में उपयोग किया जाता है।

कदलाई मितई

- कदलाई मितई एक मूंगफली की कैंडी है जो तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाती है। इस कैंडी को मूंगफली और गुड़ से तैयार किया जाता है। इसके लिए विशेष रूप से थामीबरानी नदी का पानी उपयोग किया जाता है। क्षेत्र के उत्पादकों के अनुसार इस विशेष नदी का पानी कैंडी के स्वाद को बढ़ाता है। थामीबरानी नदी पश्चिमी घाट में निकलती है और मुन्नार की खाड़ी में बहती है। यह तमिलनाडु की एक बारहमासी नदी है।

गोरखपुर का टेराकोटा

- गोरखपुर का टेराकोटा सदियों पुराना है। शहर के कुम्हार हाथी, घोड़े जैसे जानवरों की आकृतियाँ बनाते हैं। बनाई गई कला के प्रत्येक टुकड़े में अधिक मेहनत है, परन्तु इसका पारिश्रमिक अधिक नही मिलता। जीआई टैग कुम्हारों की आय बढ़ाने में मदद करेगा।

कश्मीरी केसर

- कश्मीरी केसर को जीआई टैग मिल गया है, इससे कश्मीरी केसर का निर्यात बढ़ने के साथ-साथ इसकी खेती भी बढ़ने के पूरे असार हैं। उच्च औषधीय मूल्य होने के अलावा कश्मीरी केसर पारंपरिक व्यंजनों के साथ जुड़ा हुआ है और कश्मीर के संमृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है।
- कश्मीरी केसर ने अपनी विशिष्ट गुणों जैसे उच्च सुगंध, गहरे रंग आदि के कारण अपनी पहचान बनायी है। यह केवल जम्मू और कश्मीर में उगाया जाता है। कश्मीरी केसर दुनिया में औसत समुद्र तल से 1600 मीटर से 1800 मीटर की ऊँचाई पर उगाया जाने वाला एक मात्र केसर है, जो इसकी विशिष्टता में इजाफा करता है।
- विदित हो कि कश्मीर में केसर की कृषि का इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। 500 ईसा पूर्व चीन के महान चिकित्सक वॉन जेन ने कश्मीर को केसर का घर बताया था।
- दक्षिण कश्मीर के पुलवामा पामपोर और मध्य कश्मीर के बड़गाम व श्रीनगर में भी केसर की पैदावार होती है।
- स्वीडन, स्पेन, ईरान, इटली, फ्रांस और ग्रीस में भी केसर की खूब पैदावार होता है, लेकिन कश्मीर में पैदा होने वाला केसर अपने उच्च गुणों के कारण इन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है।

02 सुंदरवन अभयारण्य में बाघों की संख्या में वृद्धि

- पश्चिम बंगाल के सुंदरवन बाघ अभयारण्य में बाघों की संख्या बढ़ी है। यहां पहले 88 बाघ होने का अनुमान लगाया गया था लेकिन अब यह बढ़कर 96 हो गए हैं। यह जानकारी वन विभाग के एक अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल का वन विभाग इस वर्तमान आंकड़े को नवंबर 2019 से जनवरी 2020 तक कराई गई गणना के आधार पर तैयार किया है।
- वन विभाग के वीडियो फुटेज के अनुसार बाघ स्वस्थ हैं। IUCN के तहत, रॉयल बंगाल टाइगर्स को लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सुंदरबन डेल्टा, जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, विश्व में बाघों का एकमात्र मैंग्रोव वन निवास हैं।

सुंदरबन

- सुंदरबन एक विश्व धरोहर स्थल और रामसर स्थल है।
- सुंदरबन का सार्वभौमिक महत्व है और यह दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। यह विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। सुंदरवन के मैंग्रोव वन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर बने हुए हैं।

ग्लोबल टाइगर फोरम

- ग्लोबल टाइगर फोरम एकमात्र अंतर-सरकारी संगठन है जो बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने में शामिल है। भारत भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इस फोरम के अनुसार, बाघों की 97% आबादी कम हो चुकी है और इनके 94% आवास स्थल नष्ट हो चुके हैं।

अन्य बाघ अभयारण्य

- उल्लेखनीय है कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर व्याघ्र अभयारण्य में भी 28 बाघ थे जो बढ़कर 31 हो गए। बीते साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर बाघों की गणना में वाल्मीकि नगर व्याघ्र अभयारण्य में बाघों की संख्या में वृद्धि बताई गई थी। यहां पर साल 2010 में बाघों की संख्या मात्र 8 थी, वहीं 2014 में यह संख्या बढ़कर 28 हुई और 2018 में यह संख्या बढ़कर 31 हो गई थी।
- साथ ही ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 में उत्तराखंड में 227 बाघ थे, जो कि वर्ष 2014 में 340 और वर्ष 2018 में बढ़कर 442 हो गए। देश के टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या के लिहाज से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पहले स्थान पर है। बता दें कि वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन में वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया था। भारत ने यह लक्ष्य चार साल पहले ही हासिल कर लिया।

03 विश्व प्रवासी पक्षी दिवस

- प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) 9 मई को विश्व प्रवासी दिवस के रूप में मनाता है। यह एक वार्षिक अभियान है जो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करता है। उल्लेखनीय है कि विश्व प्रवासी दिवस की शुरुआत पहली बार 2006 में वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन में की गयी थी।
- पक्षी मौसम के अनुसार एक राज्य या देश से दूसरे जगह प्रवास करते हैं ताकि वे अपने आपको मौसम के मुताबिक आसानी से ढाल सकें। इसे ही पक्षी प्रवास कहते हैं। हालांकि प्रवास करने के बावजूद भी उन्हें कई बार प्रदूषण और मौसम की मार झेलनी पड़ती है। पक्षियों को इन्हीं परेशानियों से निजात दिलाने और उनके संरक्षण के लिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस (World Migratory Bird Day) हर साल दो बार मनाया जाता है। इस दिवस पर प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और आवास की आवश्यकता को विश्व भर के लोगों को समझाने और जागरूक करने के लिए मई और अक्टूबर महीने के शुरू के दूसरे शनिवार को हर साल मनाया जाता है।

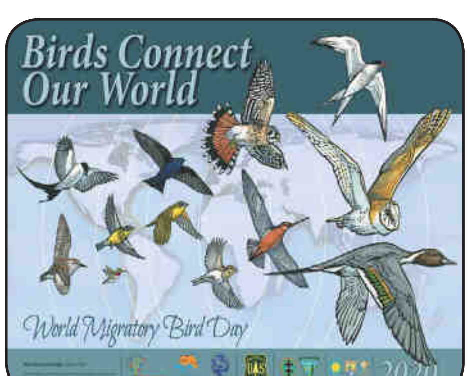

क्या है इस बार की थीम

- हर साल, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस (World Migratory Bird Day) पर एक थीम प्रस्तुत की जाती है। इस बार की थीम "पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं" (Birds Connect Our World) है।इस बार इस थीम के जरिए प्रवासी पक्षियों पर प्लास्टिक से पड़ने वाले दुष्प्रभावों को सामने लाया जाएगा और उसका समाधाम करने की कोशिश की जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक, प्लास्टिक के प्रभाव से मरने वाले समुद्री पक्षियों की संख्या वर्तमान में लगभग 1 मिलियन से ज्यादा है तथा यह बढ़ती ही जा रही है। 1960 और 1980 के बीच के दो दशकों में,

प्लास्टिक का सेवन करने वाले पक्षियों की संख्या 5% से बढ़कर 80% हो गई है।

- मानव निर्मित संरचनाएं विशेष रूप से रात में प्रवासी पक्षियों की 350 से अधिक प्रजातियों के लिए बहुत खतरा पैदा करती हैं। कांच जैसी परावर्तनशील सामग्रियों से बनी संरचनाएं कई प्रवासी पक्षियों की मौत का कारण बनती हैं। इमारतों के अलावा पवन टरबाइन भी इन पक्षियों के लिए बहुत खतरा हैं।
- भारत आने वाले 5 प्रमुख प्रवासी पक्षी, साइबेरियन सारस (Siberian Cranes), अमूर फाल्कन (Amur Falcons), राजहंस (Greater Flamingo), रोजी पेलिकन (Rosy Pelican), एशियाई कोयल (Asian Cuckoo) आदि हैं।

04 टिड्डियों का हमला

- भारत इस समय कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमा पर टिड्डियों का हमला तेज हो गया है। यह भारतीय कृषि के लिए एक संकट के रूप में सामने आया है।
- इसी वर्ष फरवरी के महीने में पंजाब और हरियाणा के खेतों में टिड्डियों के हमले की घटनाएं सामने आई थीं, जिसके चलते इन दोनों राज्यों को हाईअलर्ट पर रखा गया था।
- इसके अलावा स्थिति से निपटने और टिड्डियों के हमले के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इन दोनों राज्यों में स्पेशल सुपरविजन टीमें भी तैनात की गई।
- फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (एफएओ) की वेबसाइट के मुताबिक एक किलोमीटर फैले टिड्डी दल में करीब 40 मिलियन टिड्डे होते हैं।
- भारत ने टिड्डी से निपटने के लिए इस बार स्प्रे माउंटेड पांच हेलीकॉप्टर तैयार किए हैं।

टिड्डी (Locusts)

- मुख्यत: टिड्डी उष्णकटिबंधीय कीड़े होते हैं। ये व्यवहार बदलने की अपनी क्षमता में अपनी प्रजाति के अन्य कीड़ों से अलग होते हैं और लंबी दूरी तक पलायन करने के लिये बड़े-बड़े झुंडों का निर्माण करते हैं। टिड्डियों की प्रजाति में रेगिस्तानी टिड्डियों को सबसे खतरनाक और विनाशकारी माना जाता है। आमतौर पर जून और जुलाई के महीनों में इन्हें आसानी से देखा जाता है क्योंकि ये गर्मी और बारिश के मौसम में ही सक्रिय होते हैं।

- सामान्य तौर पर ये प्रतिदिन 150 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। यदि अच्छी बारिश होती है और परिस्थितियाँ इनके अनुकूल रहती हैं तो इनमें तेजी से प्रजनन करने की क्षमता भी होती है और ये तीन महीनों में 20 गुना तक बढ़ सकते हैं।
- उल्लेखनीय है कि राजस्थान में से 1998 में भी टिड्डी दल ने हमला किया था। वर्ष 1993 में खरीफ और रबी दोनों फसलों को इनसे काफी नुकसान हुआ था। यही कारण है कि अब जैसलमेर इलाके में टिड्डी दल को देखे जाने पर उन्हें तुरंत प्रभाव से नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है।

टिड्डी चेतावनी संगठन (Locust Warning Organization - LWO)

- इसका मुख्यालय फरीदाबाद में स्थित है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) के वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय (Directorate of Plant Protection Quarantine & Storage) के अधीन आने वाला टिड्डी चेतावनी संगठन मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में टिड्डियों की निगरानी, सर्वेक्षण और नियंत्रण के लिये जिम्मेदार है।

05 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स

- पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस की चपेट में है। इसका इलाज फिलहाल खोजा नहीं जा सका है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ही सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। इसी कड़ी में भारत ने मार्च महीने में ही लॉकडाउन घोषित कर दिया। लंदन की ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स के तहत भारत ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सबसे कड़े कदम उठाए हैं। भारत का स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स 100 है जो कि सबसे ज्यादा है।

क्या होता है स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स

- किसी भी समस्या से निपटने के लिए किसी सरकार ने कितने कड़े कदम उठाए हैं, इसके आधार पर स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स निकाला जाता है। कोरोना वायरस की त्रासदी से निपटने के लिए कुछ जरूरी कदम माने गए हैं। इसके स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स के लिए 7 कदम ध्यान में रखे गए हैं- स्कूल, वर्कप्लेस, पब्लिक इवेंट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जागरूकता अभियान, घरेलू ट्रैवल और इंटरनेशनल ट्रैवल पर बंदी। जिस देश ने जितने कड़े कदम उठाए होते हैं, यह इंडेक्स उतना ज्यादा होता है।
- इसके आधार पर भारत का स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स 1000 केस होने से पहले ही 100 पर पहुंच गया था। दूसरी तरफ, अमेरिका का इंडेक्स अभी भी 66.7 है जहां इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं, ब्रिटेन का इंडेक्स 71.4, जर्मनी और साउथ कोरिया का 81 है। सबसे ज्यादा मौतें देख चुके इटली में इंडेक्स 95.2 पहुंचा

है। भारत के अलावा 17 देशों का इंडेक्स 100 पर है।

- भारत में 26 मार्च को 21 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। इसके चलते स्कूल, दफ्तर, रेस्तरां, मॉल समेत सब ऐसे संस्थान और सेवाएं बंद कर दी गई थीं जो जरूरी सेवाओं या सामान में नहीं आती थीं। यही नहीं, मामले बढ़ने के साथ ही देश के कई हिस्सों में हॉटस्पॉट्स की पहचान करके सील कर दिया गया है। भारत के इस कदम की दुनियाभर में तारीफ हो रही है। माना जा रहा है कि इतनी बड़ी आबादी वाले देश के लिए यह फैसला कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक अहम कदम साबित हो सकता है।

06 विशारवापट्टनम के केमिकल प्लांट में स्टाइरीन गैस का रिसाव

- आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित एलजी पॉलिमर के प्लांट में अचानक स्टाइरीन गैस लीक होने से बड़ा हादसा हो गया। एनडीआरएफ ने विशाखापट्टनम गैस रिसाव के चलते अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि की है।
- उल्लेखनीय है कि हिंदुस्तान पॉलिमर कंपनी की स्थापना 1961 में हुई थी। 1997 में कंपनी को साउथ कोरिया के एलजी केमिकल ने टेकओवर कर लिया था और इसे एलजी पॉलिमर नाम दिया था। प्लांट में प्लास्टिक बनाने का काम होता है।

स्टाइरीन गैस क्या है?

- स्टाइरीन मूल रूप में पॉलिस्टाइरीन प्लास्टिक और रेजिन बनाने में इस्तेमाल होती है। यह रंगहीन या हल्का पीला ज्वलनशील लिक्विड (द्रव) होता है। इसकी गंध मीठी होती है। इसे स्टाइरोल और विनाइल बेंजीन भी कहा जाता है। बेंजीन और एथिलीन के जरिए इसका औद्योगिक मात्रा में यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। स्टाइरीन का इस्तेमाल प्लास्टिक और रबड़ बनाने में होता है। इन प्लास्टिक या रबड़ का इस्तेमाल खाने-पीने की चीजें रखने वाले कंटेनरों, पैकेजिंग, सिंथेटिक मार्बल, फ्लोरिंग, डिस्पोजेबल टेबलवेयर और मोल्डेड फर्नीचर बनाने में होता है।
- स्टाइरीन की भाप अगर हवा में मिल जाए तो यह नाक और गले में जलन पैदा करती है। इससे खांसी और गले में तकलीफ होती है और साथ ही फेफड़ों में पानी भरने लगता है। अगर स्टाइरीन ज्यादा मात्रा में सांस के जरिए शरीर में पहुंचती है तो यह स्टाइरीन बीमारी पैदा कर सकती है। इसमें सिरदर्द, जी मिचलाना, थकान, सिर चकराना, कनफ्यूजन और पेट की गड़बड़ी होने जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। इन्हें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन कहा जाता है। कुछ मामलों में स्टाइरीन के संपर्क में आने से दिल की धड़कन असामान्य होने और कोमा जैसी स्थितियां तक बन सकती हैं।
- स्टाइरीन त्वचा के जरिए भी शरीर में दाखिल हो सकती है। अगर त्वचा के जरिए शरीर में इसकी बड़ी मात्रा पहुंच जाए तो सांस लेने के जरिए पैदा होने वाले सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अगर स्टाइरीन पेट में पहुंच जाए तो भी इसी तरह के असर दिखाई देते हैं।
- कई अध्ययनों से यह पता चला है कि स्टाइरीन के संपर्क में आने से ल्यूकेमिया और लिंफोमा का भी जोखिम बढ़ सकता है।

07 यूरोपीय संघ के न्यायालय (सीजेईयू)

- हाल ही में जर्मनी की संवैधानिक अदालत ने यूरोपीय न्यायालय (सीजेईयू) के एक फैसले की वैधता पर सवाल उठाया है। यह सवाल यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) की एक बॉन्ड-खरीद योजना के संबंध में उठाया गया है। उल्लेखनीय है कि यूरो और यूरोपीय संघ के राष्ट्रीय बाजारों में वर्ष 2010 में आये संकट के समय ईसीबी द्वारा बड़े पैमाने पर बॉन्ड-खरीद की शुरूआत की गई थी। यह शुरूआत ग्रीस तथा अन्य देशों को सहायता राशि (Bell out Package) प्रदान करने के लिए की गई थी। इसी के तहत वर्ष 2019 में ईसीबी ने 2.1 ट्रिलियन का बॉण्ड जारी किया था। इसी खरीद को लेकर कुछ यूरोपीय देश अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जर्मनी की संवैधानिक अदालत का कहना है कि इसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। उनका

यह भी कहना है कि जब तक इस बॉण्ड की आवश्यकता को नहीं बताया जाता, तब तक के लिए इस पर रोक लगा देना चाहिए। ध्यातव्य है कि सीजेईयू ने 2018 में यह फैसला दिया था कि ईसीबी बांड की बिक्री यूरोपियन संघ के कानून के अनुसार है।

- यूरोपीय संघ के न्यायालय (सीजेईयू) यूरोपीय संघ (ईयू) की संस्था है जो पूरे न्यायपालिका को शामिल करती है।
- सीजेईयू यूरोपीय संघ का मुख्य न्यायिक प्राधिकरण है और सदस्य राज्यों की राष्ट्रीय न्यायपालिका के सहयोग से यूरोपीय संघ कानून के समान आवेदन और व्याख्या की देखरेख करता है। सीजेईयू राष्ट्रीय सरकारों और ईयू संस्थानों के बीच कानूनी विवादों का भी समाधान करता है, और व्यक्तियों, कंपनियों या संगठनों के पक्ष में ईयू संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई कर करता है जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।
- 1 दिसंबर 2009 को लिस्बन की संधि के बाद, ECJ का आधिकारिक नाम Court of Justice of the European Communities से Court of Justice में बदल दिया गया था। वर्तमान में इसके 27 सदस्य हैं।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न
(मुख्य परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 स्वामित्व योजना क्या है? यह योजना भारत के किसानों के सशक्तिकरण के लिए किस प्रकार सहायक है? चर्चा करें।

02 हाल ही में वैश्विक पोषण रिपोर्ट-2020 जारी किया गया। इस रिपोर्ट के संदर्भ में भारत तथा विश्व में पोषण की स्थिति पर प्रकाश डालें।

03 हाल ही में भारतीय बैंक संघ ने वित्त मंत्रालय को ‘बैड बैंक’ का निर्माण करने की सिफारिश की है। ‘बैड बैंक’ को समझाते हुए यह बतायें कि यह बैंकों के लिए किस प्रकार लाभदायक होगा?

04 हाल ही में केन्द्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने तथा अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है। यह पैकेज जनजीवन को फिर से पटरी पर लाने में किस प्रकार महत्वपूर्ण साबित होगा? उल्लेख करें।

05 ‘आत्मनिर्भर अभियान’ क्या है? भारत को अपनी आर्थिक हालत सुधारने में यह अभियान कितना सहायक होगा? चर्चा करें।

06 हाल ही में डब्लूइएफ (WEF) द्वारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया गया। इस इंडेक्स के संदर्भ में भारत में ऊर्जा सुरक्षा, और पर्यावरणीय स्थिरता पर प्रकाश डालें।

07 हाल ही में चर्चा में रहा ‘उद्योग 4.0’ क्या है? इसे अपनाने में आने वाली चुनौतियों तथा उसके लाभों का विस्तार से चर्चा करें।

7 महत्वपूर्ण तथ्य
(प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

01 झारखंड ने किस हानिकारक रसायन पर अंकुश लगाने हेतु एक वर्ष के लिए 11 ब्रांडों के पान मसाले के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया?

मैग्नीशियम कार्बोनेट

02 हाल ही में किस सशस्त्र बल द्वारा निर्मित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का एक किफायती मॉडल नैदानिक उपयोग के लिए प्रमाणित किया गया है?

भारतीय नौसेना

03 हाल ही में सुर्खियों में रही 'मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना' किस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की एक पहल है?

त्रिपुरा

04 29वाँ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस (National Technology Day) 2020 किस दिन मनाया गया?

11 मई

05 हाल ही में गोवा के नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य (Netravali Wildlife Sanctuary) में पहली बार किसकी उपस्थिति पाई गई?

'ब्लैक पैंथर' (Black Panther)

06 रूस की 'लावोस्किन एयरोस्पेस कंपनी' ने आर्कटिक जलवायु एवं पर्यावरण निगरानी के लिये कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है?

आर्कटिक-एम (Arktika-M)

07 पीरामल फाउंडेशन' (Piramal Foundation) के सहयोग से नीति आयोग (Niti Aayog) ने COVID-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कौन सा अभियान प्रारंभ किया है?

सुरक्षित दादा-दादी एवं नाना-नानी अभियान

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

03
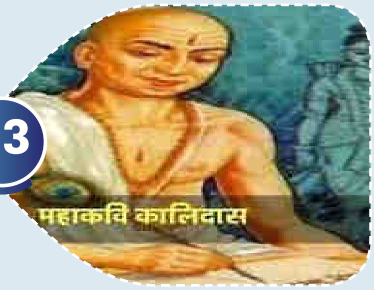

05
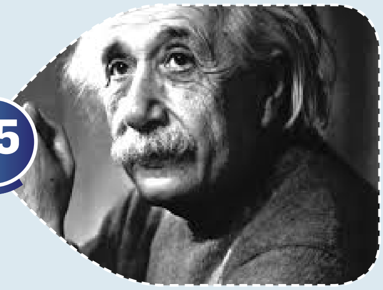

07
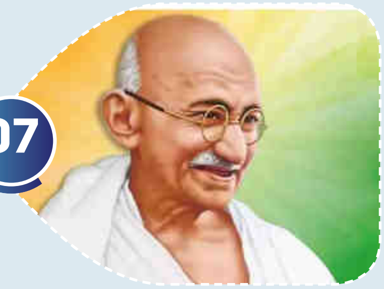

01 मै ऐसे धर्म को मानता हूँ, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है।

चंद्रशेखर आजाद

02 जिस समाज में कोई अमीर या कोई गरीब नहीं होता है, वहां लोगों में सिर्फ अच्छे संस्कार पाए जाते हैं।

प्लेटो

03 राज्य छाते के समान होता है, जिसका अपने हाथ में पकड़ा हुआ करदंड कई बार उतनी समस्याओं से रक्षा नहीं करता, जितनी कि थकान उत्पन्न कर देता है।

कालिदास

04 मन कभी भी इच्छित वस्तु प्राप्त होने के बाद भी संतुष्ट नही होता जैसे किसी फूटे हुए बर्तन में चाहे कितना भी पानी भर दिया जाय लेकिन वह कभी नहीं भरता।

महर्षि बाल्मीकि

05 जीवन जीने के दो तरीके हैं पहला मानकर चलो की जो कुछ हो रहा है वह चमत्कार है और दूसरा कोई चमत्कार नही है सब निर्धारित है।

अल्बर्ट आइंस्टीन

06 जितना अधिक श्रम का विभाजन और मशीनरी का उपयोग बढ़ता है, उतना ही श्रमिकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और उतना ही उनका वेतन कम होता जाता है।

कार्ल मार्क्स

07 एक देश की महानता और नैतिक प्रगति को इस बात से आँका जा सकता है कि वहाँ जानवरों से कैसे व्यवहार किया जाता है।

महात्मा गाँधी

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the Institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR-8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333,7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter
(ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |